https://www.facebook.com/KamalSandeshBjp/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

प्रधानमंत्री की पुर्तगाल, अमेरिका और नीदरलैंड की सफल यात्रा

वर्ष-12, अंक-14, 16-31 जुलाई, 2017 (पाक्षिक) ₹20

'मो बूथ सबूठू मजबूत'

'ओडिशा को उन्नत राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है भाजपा'

भारत में ऐतिहासिक 'जीएसटी' की शुरुआत

एकात्मता की चिर साधना

जीएसटी: गरीबों के उत्थान में सहायता प्रदान करने का महान साधन

ओडिशा, गोवा एवं पुदुच्चेरी में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के प्रवास की झलकियां

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in
mail@kamalsandesh.com
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 **ओडिशा के युवाओं को अपने राज्य में ही रोजगार की सुविधा मिले: अमित शाह**

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने ओडिशा के अपने तीन दिवसीय बूथ प्रवास कार्यक्रम के दौरान 5 जुलाई को गंजम जिले के हुगुलापता गांव में घर-घर जाकर जनसंपर्क किया और घरों में स्टिकर...

वैचारिकी

एकात्मता की चिर साधना 16

श्रद्धांजलि

बाल गंगाधर तिलक 18

लेख

जीएसटी: गरीबों के उत्थान में सहायता प्रदान करने का महान साधन 22

अन्य

प्रधानमंत्री की पुर्तगाल, अमेरिका और नीदरलैंड की सफल यात्रा 19

'जीएसटी की शुरुआत राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण घटना' 24

सहकारी संघवाद की अद्भुत मिसाल 'जीएसटी': नरेंद्र मोदी 26

'वस्तु और सेवा कर' एक महत्वाकांक्षी कर सुधार: अरुण जेटली 30

लोकतंत्र की विरासत को हमें और सशक्त करना है: नरेंद्र मोदी 32

संगठनात्मक गतिविधियां

10 **'गोवा में सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन भी हुआ है'**

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने अपने दो दिवसीय गोवा...

11 **'तीन सालों में हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा पाये'**

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री...

सरकार की उपलब्धियां

13 **भारत में ऐतिहासिक 'जीएसटी' की शुरुआत**

संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित ऐतिहासिक मध्य रात्रि सत्र के बीच 30 जून की मध्य रात्रि...

33 **मनरेगा के तहत 2017-18 में 86 फीसदी मजदूरी का भुगतान समय से किया गया**

मनरेगा के तहत, अप्रैल से जून 2017 में खासकर...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

'जीएसटी', टीम इंडिया की शक्ति को प्रदर्शित करता है। यह दिखाता है कि कैसे केंद्र व राज्य मिलकर गरीबों की भलाई के कार्य कर सकते हैं।

@arunjaitley

'क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल' के सफल उड़ान परीक्षण से जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के पूर्ण स्वदेशीकरण का रास्ता सुगम हो गया है।

@JPNadda

परिवर्तन रथ यात्रा के पांवटा साहिब आगमन पर जनसभा को संबोधित किया। प्रदेश की माफ़िया सरकार से जनता त्रस्त हो गयी है, परिवर्तन का समय निकट है।

facebook

नर्मदा सेवा अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 6 करोड़ पौधे लगाने के विश्व के सबसे बड़े पौधारोपण महाभियान के लिए मैं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को बधाई देता हूं। प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण सुधार के साथ-साथ मां नर्मदा के संवर्धन के लिए यह एक अद्भुत पहल है, जिसको शिवराज सिंह जी ने जन-भागीदारी से एक जन-अभियान का रूप दिया है। जल और वृक्ष मानव जीवन के अभिन्न अंग है और इनके बिना जीवन अकल्पनीय है, इसलिए इन्हें संरक्षित करना न सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि हमारा कर्तव्य भी है।

— अमित शाह

प्रदेश में हर परिवार को उसके हक़ का राशन मिले और पूरा मिले इसके लिए सरकार ने बायोमैट्रिक पहचान से राशन वितरण शुरू किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र व्यक्ति मशीन पर अंगूठा या अंगुली लगाकर राशन प्राप्त कर रहे हैं। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार की है। अपात्र व्यक्ति सूची से हट गये हैं। मेरा राशन, मेरा हक़।

—वसुंधरा राजे

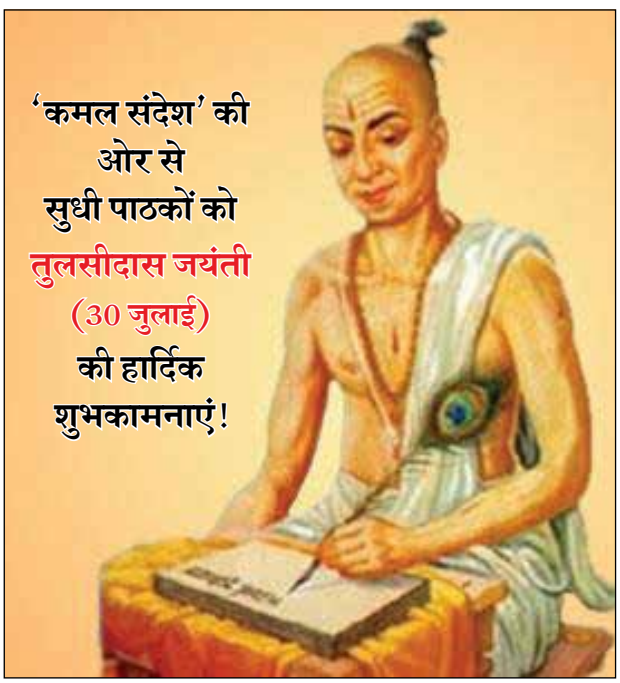

जीएसटी : एक क्रांतिकारी पहल

माल एवं सेवाकर (गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स– जीएसटी) के लागू होने से भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर बदलने वाली है। 'एक राष्ट्र, एक कर' के घोष वाक्य के साथ शुरू हुआ यह अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ना निश्चित है। यह बहुत ही कठिन कदम था तथा इसमें इतनी अधिक जटिलताएं थी कि इस पर आम सहमति बनाकर एक कानून में ढालना लगभग असंभव सा प्रतीत होता था। जिस प्रकार से आम सहमति की प्रक्रिया चली और अंततः सफल हुई उससे सरकार के 'सहकारी संघवाद' के सिद्धांतों पर गहरा विश्वास प्रकट होता है। भिन्न–भिन्न प्रकार और यहां तक की विपरीत अपेक्षाओं एवं हितों में सामंजस्य बना पाना इस प्रक्रिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। 'सबका साथ, सबका विकास' के सिद्धांतों पर खरे उतरे बिना यह असंभव था, लेकिन यह आश्चर्यजनक रूप से सफल हो पाया जिसमें सभी के लिए लाभ की स्थिति बन पाई है। उपभोक्ताओं को जहां कम कर देना पड़ेगा, राज्य और केन्द्र सरकार को कर के व्यापक आधार से अधिक कर संग्रह में सहायता मिलेगी। व्यापार एवं उद्योग–धंधे करों के जंजाल से बाधामुक्त होकर बड़ी छलांग लगा सकते हैं। 'इज ऑफ डूविंग बिजनेस' में व्यापक परिवर्तन से अर्थव्यवस्था सुविधापूर्ण एवं व्यापार के लिए उचित वातावरण तैयार होगा। वास्तव में यह एक ऐसे दौर की शुरूआत है, जिसमें सबके लिये लाभ ही लाभ है और भारतीय अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होगी उतनी ही सुविधापूर्ण भी बन गई है। आने वाले दिनों में जीएसटी से हर क्षेत्र में व्यापक बदलाव होना तय है।

> प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जीएसटी को ठीक ही 'गुड एण्ड सिंपल टैक्स' की संज्ञा दी है। इससे न केवल देश के गरीबों पर कर भार का वजन कम हुआ है, बल्कि एक ऐसे सरल व्यवस्था की रचना हुई है जिसमें करदाता खुशी–खुशी देश के विकास में अपना योगदान कर पायेंगे।

जीएसटी देश में अभूतपूर्व राजनैतिक आम सहमति के लिये भी जानी जायेगी। विभिन्न राजनैतिक दलों का दलगत राजनीति से ऊपर उठकर साथ आना जहां राजनैतिक परिपक्वता की निशानी है वहीं एक सुदृढ़ लोकतंत्र की पहचान भी है। इससे यह पता चलता है कि सुशासन एवं विकास पर पूरा भारत एकजुट है, परन्तु जिस प्रकार से कांग्रेस ने अंतिम समय में आचरण किया उससे पुनः यह स्पष्ट होता है कि यह राष्ट्रीय हित के ऊपर अपनी राजनीति करने से परहेज नहीं करती। उद्घाटन समारोह में शामिल होने से इंकार कर कांग्रेस नेतृत्व ने अपने असमंजस की स्थिति को ही उजागर किया है। हालांकि, इसने जीएसटी का समर्थन किया था, पर यह अंदाजा नहीं लगा पाई थी कि सरकार इतने कम समय में इसे सफलतापूर्वक लागू कर पायेगी। अब जबकि कांग्रेस को पूरे जोर–शोर से जीएसटी का समर्थन करना चाहिये था, यह जीएसटी पर असंतोष को हवा देने में लगी हुई है। इस पूरी प्रक्रिया में कांग्रेस का दोहरा चेहरा सामने आया है। परिणामस्वरूप जदयू, जद(सेकुलर), एनसीपी जैसे अनेक राजनैतिक दलों ने कांग्रेस के इस निर्णय का साथ नहीं दिया। एक ओर जहां पूरे देश में जीएसटी के लागू होने पर उत्सव का माहौल था, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अलग–थलग पड़ी हुई थी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जीएसटी को ठीक ही 'गुड एण्ड सिंपल टैक्स' की संज्ञा दी है। इससे न केवल देश के गरीबों पर कर भार का वजन कम हुआ है, बल्कि एक ऐसे सरल व्यवस्था की रचना हुई है जिसमें करदाता खुशी–खुशी देश के विकास में अपना योगदान कर पायेंगे। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल एजेंसी 'मूडी' ने इसका पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि इससे भारत की छवि सकारात्मक बनेगी, विकास दर बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी तथा आसान कर भुगतान व्यवस्था से सरकार अधिक कर भी प्राप्त कर पायेगी। कॉन्फेडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई) ने भरोसा जताया है कि इससे व्यापार में तेजी आयेगी तथा उद्योग–धंधे बढ़ेंगे। इससे हर ओर एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण हुआ है तथा देश के अंदर एवं बाहर लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस प्रक्रिया से जुड़े हर किसी की भूरि–भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे निर्यात की स्पर्धात्मकता बढ़ेगी तथा घरेलू उद्योगों को आयातों से स्पर्धा करने में मजबूती मिलेगी। बाजार ने भी इसका स्वागत अच्छे संकेतों से किया है और इसके प्रभावी क्रियान्वयन से पुनः यह बात सिद्ध हुई है कि यदि नेतृत्व में कड़े और निर्णयात्मक कदम उठाने की राजनैतिक इच्छाशक्ति हो तो भारत भी बड़े और परिवर्तनकारी निर्णय ले सकता है। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

ओडिशा के युवाओं को अपने राज्य में ही रोजगार की सुविधा मिले: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने ओडिशा के अपने तीन दिवसीय बूथ प्रवास कार्यक्रम के दौरान 5 जुलाई को गंजम जिले के हुगुलापता गांव में घर-घर जाकर जनसंपर्क किया और घरों में स्टिकर चिपकाए. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की तीन वर्ष की उपलब्धियों को भी जनता से साझा किया और इससे संबंधित बुकलेट भी बांटे। जनसंपर्क करने के बाद श्री शाह ने हुगुलापता गांव में बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं से 2019 में दो तिहाई बहुमत से ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का आह्वान किया। तत्पश्चात उन्होंने बीडीए ग्राउंड विवेक विहार, बरहामपुर में ओडिशा के चार जिलों से आये बूथ कार्यकर्ताओं के विशाल सम्मेलन को संबोधित किया। इसके पूर्व भाजपा अध्यक्ष ने ओडिशा पंचायत चुनाव के दौरान राजनीतिक हिंसा में शहीद हुए भाजपा के युवा कार्यकर्ता श्री चित्रसेन जेना की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने शहीद श्री चित्रसेन जेना की मां से मुलाक़ात कर उनका नमन किया और उन्हें सांत्वना दी। विदित हो कि 20 वर्षीय श्री जेना खोरधा (खुर्दा) जिला के बड़ापोखरिया गांव के निवासी थे जिनकी ओडिशा पंचायंत चुनाव के दौरान निर्मम हत्या कर दी गई थी।

बरहामपुर में ओडिशा के चार जिलों से आये बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और संगठन के कार्यकर्ताओं की ओर से महाप्रभु जगन्नाथ की इस पवित्र भूमि को हृदय से नमन करता हूं और ओडिशा एवं ओडिशा की जनता के कल्याण के लिए उनसे आशीर्वाद की याचना करता हूं। उन्होंने कहा कि आज ओडिशा में मैं जहां भी गया, ओडिशा की जनता के दिल में भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्यार ही प्यार देखा। उन्होंने कहा कि ओडिशा की जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्यार,

2014 में श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में जहां-जहां चुनाव हुए, लगभग हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी चाहे वह महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, जम्मू-कश्मीर हो, असम हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो या फिर मणिपुर।

समर्थन और आशीर्वाद देखकर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस बार राज्य में 2019 में भारतीय जनता पार्टी की दो तिहाई बहुमत की सरकार बनने जा रही है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में जहां-जहां चुनाव हुए, लगभग हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी चाहे वह महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, जम्मू-कश्मीर हो, असम हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो या फिर मणिपुर। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा 2019 में ओडिशा पहुंचेगी तो यहां भी परिवर्तन होगा और भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव में जब परिवर्तन की बात करते हैं तो यह परिवर्तन किसी विधायक, मंत्री अथवा मुख्यमंत्री को बदलने के लिए नहीं होता, बल्कि राज्य की स्थिति में परिवर्तन के लिए होता है। उन्होंने कहा कि इसी तरह जब हम ओडिशा में परिवर्तन की बात करते हैं तो हम ओडिशा की स्थिति में परिवर्तन लाने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ओडिशा में गरीबी को दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, हर घर में शुद्ध पीने का पानी और शौचालय की व्यवस्था करने के लिए, हर गरीब घर में एक रुपये किलो चावल पहुंचाने के लिए, हर गांव में 24 घंटे बिजली पहुंचाने के लिए परिवर्तन लाना चाहती है। उन्होंने कहा कि देश में जिन-जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां हमने विकास करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि ओडिशा में केवल 14% लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिल रहा है, 36% गांव आज भी अंधेरे में जीने को विवश हैं, केवल एक चौथाई घरों में शौचालय है, लगभग 46% आबादी आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि ओडिशा की स्थिति में यदि परिवर्तन लाना है तो राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजू जनता दल (बीजद) ओडिशा में गरीबों के घर में न चावल पहुंचा सकती है, न पीने का पानी और न ही बिजली, यह केवल और केवल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही सकती है।

श्री शाह ने कहा कि गुजरात सहित देश के कई राज्यों के विकास में ओडिशा के युवा भाइयों का पसीना है, लेकिन क्या कारण है कि ओडिशा के मेहनतकश युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करने को विवश हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ओडिशा के युवाओं को अपने राज्य में ही रोजगार की सुविधा मिले।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश भर में स्वच्छता अभियान शुरू किया हुआ है, उनका कहना है कि देश में गरीब से गरीब महिलाओं को शौचालय की सुविधा मिलनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि ओडिशा में सिर्फ 22% घरों में ही शौचालय है, समझ में नहीं आता कि इतने सालों तक ओडिशा में शासन करने के बाद आखिर कांग्रेस और बीजद ने ओडिशा के लिए किया ही क्या है।

श्री शाह ने कहा कि ओडिशा में 3500 से ज्यादा डॉक्टरों की जगह खाली है, स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था राज्य में नहीं है। उन्होंने कहा कि दाना माझी सरीखी घटनाएं अंतरात्मा को झकझोर कर रख देती है, जब एक मृत शरीर को भी आप सम्मान नहीं दे सकते, तो आप आखिर क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि ओडिशा देश के समृद्ध राज्यों में से एक है लेकिन ओडिशा की जनता गरीब है, आखिर ओडिशा की धन-संपदा जाती कहां है - यह कहीं चिटफंड घोटाले में चली जाती है तो कहीं खनन घोटाले में। उन्होंने कहा कि ओडिशा की उर्वरा धरती के नीचे खनन की जितनी संभावनाएं हैं, उतना देश में कहीं भी नहीं है, लेकिन इसके वाबजूद ओडिशा का विकास नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि ओडिशा में एक ऐसी सरकार चाहिए जो दूरदर्शी हो, विकासोन्मुख हो और जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कंधे से कंधा मिलाकर ओडिशा की भलाई के लिए सदैव तत्पर हो और इस तरह की शासन-वाव्यस्था केवल भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। उन्होंने कहा कि ओडिशा की जनता इस तथ्य को अब भलीभांति समझ चुकी है इसलिए ओडिशा में हुए स्थानीय निकाय के चुनावों में राज्य की जनता ने कांग्रेस का सूपड़ा तो साफ़ कर ही दिया, साथ ही सत्ताधारी बीजद को भी बैकफुट पर धकेल दिया है।

उन्होंने कहा कि ओडिशा में 30 जिला पंचायतों में से भाजपा पहले एक भी जिला पंचायत में नहीं थी, वहीं आज भाजपा आठ जिला पंचायतों पर बहुमत से काबिज है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय के चुनावों में भाजपा को 356 से अधिक सीटें देकर ओडिशा की जनता ने राज्य में परिवर्तन के संकेत पहले ही दे दिए हैं। कालाहांडी में स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कालाहांडी में गरीबी दूर करने का वादा करके गए थे, लेकिन परिणामों में कांग्रेस ही कालाहांडी की जनता से दूर चली गई, कालाहांडी की जनता ने 36 में से 34 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने ओडिशा में रेलवे के विकास के लिए पहले दो साल हर वर्ष 3700 करोड़ रुपये और 2017-18 में 5100 करोड़ रुपये देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 10 वर्षों के शासनकाल में ओडिशा को जितना दिया, उससे दुगुनी आर्थिक सहायता मोदी सरकार ने केवल तीन साल में ही ओडिशा के लिए आवंटित कर दी है। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 सालों में ओडिशा में केवल 4500 किलोमीटर सड़क का ही निर्माण हुआ, जबकि मोदी सरकार के तीन साल में 4800 किलोमीटर सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई, इनमें से कई सड़कें शुरू भी हो गई है। उन्होंने कहा कि ओडिशा में छह राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए मोदी सरकार ने दो हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य में 7000 किलोमीटर की सड़क बनाई गई है। उन्होंने कहा कि श्री धर्मेन्द्र प्रधान देश के पेट्रोलियम मंत्री हैं, अकेले पेट्रोलियम मंत्रालय ने ओडिशा में पांच साल के अन्दर 1,26,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना में ओडिशा में 762 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाई जायेगी, जिससे ओडिशा के 13 राज्यों को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ओडिशा में 13 लाख गरीब माताओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है, 2019 से पहले ओडिशा की 30 लाख गरीब माताओं को गैस कनेक्शन देने का काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ओडिशा में 8000 करोड़ रुपये की लागत से फर्टिलाइजर का कारखाना लगाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, इस कारखाने से 13 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होगा। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम

विद्युतीकरण योजना के तहत आजादी के बाद पहली बार ओडिशा के 2439 गांवों को रोशन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि कोयला मंत्रालय के अन्दर राज्य को रॉयल्टी के रूप में ओडिशा को लगभग 73,166 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि खनन के नियमों के तहत आदिवासी

भाइयों की भलाई के लिए हर जिले में एक खनन समिति गठित की जायेगी जो ट्राइबल्स के विकास की योजनायें बनायेगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ओडिशा में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 600 करोड़ रुपये देने का काम किया है। वाणिज्य मंत्रालय ने भी ओडिशा में 3816 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि ओडिशा के विकास के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाये गए क़दमों की सूची बहुत लंबी है, लेकिन मोदी जी द्वारा ओडिशा के विकास के लिए जो धनराशि दी जा रही है, वह ओडिशा की जनता तक पहुंच पायेगी, इसमें संदेह है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तीन साल में देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, आदिवासी, युवा एवं महिलाओं की भलाई के लिए 106 लोक-कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है और इन योजनाओं के माध्यम से ओडिशा का विकास होने वाला है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार जीएसटी लेकर आई है, इसका सबसे ज्यादा फायदा यदि किसी राज्य को मिलने वाला है तो वह ओडिशा को होगा।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तीन साल में कई ऐतिहासिक काम किये हैं चाहे वह वन रैंक, वन पेंशन योजना को लागू करने की बात हो या फिर पाकिस्तान से लगी सीमा को सुरक्षित करने की बात हो। उन्होंने कहा कि पाक प्रेरित आतंकवादी पहले देश के अंदर घुसकर गोलीबारी करके चले जाते थे, लेकिन उरी की घटना के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और हमारे जवानों की अप्रतिम बहादुरी ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री दुनिया में कहीं भी जाते हैं, हजारों-हजार का हुजूम उनके स्वागत के लिए तैयार रहता है, यह 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दुनिया में भारत के मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि वह इस बार ओडिशा में परिवर्तन करके रहेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बार केवल सरकार बनाने के लिए चुनाव में न उतरे, बल्कि 120 सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर चुनाव में उतरे। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के रूप में दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी के पास है, हम उनके नेतृत्व में राज्य के सभी 36 हजार बूथों में कमल का झंडा और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ आंधी की तरह फ़ैल जाएं और विजयी होकर 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन करें।

इससे पहले गंजम जिले के हुगुलापता गांव में बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि ओडिशा की जनता में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं यहां एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नहीं, बल्कि एक विस्तारक के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में आया हूं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैं बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहा हूं, उसी तरह देश भर में चार लाख से अधिक कार्यकर्ता एक साल, छह महीने और 15 दिन के लिए पूर्णकालिक के रूप में पार्टी को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितना बजट ओडिशा को 25 साल में भारत सरकार ने नहीं दिया होगा, उतना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओडिशा को तीन साल में ही देने का काम किया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि जब तक ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले लेते, तब तक हमें आराम करने का अधिकार नहीं है। ■

'बीजद को उखाड़ फेंकेगी भाजपा'

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने राज्य की बीजद सरकार पर तीखा हमला किया। जाजपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि बीजू जनता दल के शासन में ओडिशा का विकास नहीं हो पा रहा है, यहां बेरोजगारी है, स्वास्थ्य और शिक्षा का बुरा हाल है। उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर पटनायक सरकार को घेरा और कहा कि ओडिशा की मौजूदा सरकार राज्य का विकास नहीं कर पा रही है। श्री शाह ने कहा कि खनिज संपदाओं की भरमार होने के बावजूद सूबा पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि 2019 में ओडिशा में भाजपा दो तिहाई बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।

'गोवा में सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन भी हुआ है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने अपने दो दिवसीय गोवा प्रवास के दौरान 2 जुलाई को मडगांव स्थित दक्षिणी गोवा जिला भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया और विश्वास व्यक्त किया कि यह जिला कार्यालय गोवा में संगठन की मजबूती का कारक बनेगा। इससे पहले श्री शाह ने गोवा भाजपा के आईटी सेल और मीडिया सेल की बैठक की। उन्होंने विभागों व प्रकल्पों की भी बैठक की और राज्य में पार्टी की चल रही गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की। श्री शाह ने सलिगाव में आधुनिक वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का भी निरीक्षण किया, जो नॉर्थ गोवा जिले के तटीय इलाके से प्रतिदिन सैकड़ों टन कचरे का निस्तारण करता है।

दक्षिणी गोवा जिला भाजपा कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित जन-समुदाय एवं पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जन संघ से भारतीय जनता पार्टी की शून्य से शिखर तक की यात्रा के मूल में पार्टी के ऊर्जावान एवं निष्ठावान कार्यकर्ता ही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब पार्टी के साथ जुड़ते हैं, तो एक परिवार की तरह जुड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज इस जिला कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर कार्यकर्ताओं के चेहरे पर वैसा ही आनंद प्रतीत हो रहा है, जैसे उनके अपने घर के वास्तु-पूजन के समय होता है और यही बात भारतीय जनता पार्टी को अन्य पार्टियों से सबसे अलग बनाती है। उन्होंने कहा कि बाकी सारी पार्टियां भले ही नेताओं और नेतृत्व के आधार पर चलती होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व ही पार्टी के छोटे से छोटे बूथ के एक सामान्य कार्यकर्ता के अंदर बसा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए यह कार्यालय महज कोई सीमेंट-पत्थर से बना हुआ एक मकान नहीं है, पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए यह एक मंदिर के समान है, क्योंकि यहां पार्टी के कार्य का रेखांकन होता है, योजनायें बनती हैं और उसी के आधार पर पार्टी आगे बढ़ती है। उन्होंने कहा कि इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि देश के हर जिले में पार्टी कार्यालय बनाने का काम दिसंबर, 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यालय पार्टी की योजनाओं को मूर्त रूप देने का साधन होते हैं।

श्री शाह ने कहा कि किसी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो उस राज्य में केवल सत्ता परिवर्तन ही नहीं होता, बल्कि उस राज्य की व्यवस्था में भी परिवर्तन होता है और गोवा इसका एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि पांच साल पहले यहां भाजपा की सत्ता स्थायी रूप से आई थी, हम फिर से दुबारा जीत कर आये हैं। उन्होंने कहा कि जब से हमने गोवा में शासन की कमान संभाली है, तब से गोवा का विकास दिन दुगुना, रात चौगुना हो रहा है। उन्होंने कहा कि विकास के बहुत सारे प्रोजेक्ट श्री मनोहर पर्रिकर और श्री लक्ष्मीकांत पारसेकर

के नेतृत्व में शुरू हुए और संपन्न हुए। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से मनोहर जी के नेतृत्व में गोवा के विकास की यात्रा आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विकास होना एक बात है, कई राज्यों में विकास हुए हैं, लेकिन गोवा में भाजपा सरकार बनने के साथ ही एक और काम शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि गोवा के आम-जन की आकांक्षाओं के अनुरूप विकास करने वाली सरकार तो श्री मनोहर पर्रिकर के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही बन गई, लेकिन उसके साथ-साथ भ्रष्टाचार नाम के शब्द को गोवा की सरहदों से दूर करने वाली सरकार भी गोवा में बनी है। उन्होंने कहा कि श्री मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में गोवा की भाजपा सरकार पारदर्शी और भ्रष्टाचार विहीन सरकार है, भाजपा ने राज्य को एक आम नागरिक जैसा मुख्यमंत्री देने का काम किया है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि गोवा भले ही एक छोटा राज्य है, लेकिन गोवा में इस बात की पूरी संभावना है कि वह एक मॉडल स्टेट के रूप में देश में प्रतिष्ठित हो सके। उन्होंने कहा कि मुझे कहते हुए आनंद है कि श्री मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में गोवा तेज गति से एक मॉडल स्टेट बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और जल्द ही गोवा देश में सभी राज्यों के लिए विकास का एक मॉडल स्टेट बनकर उभरेगा।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गोवा में इन्फ्रास्ट्रक्चर की सभी परियोजनाओं को तेज गति से पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराये गए हैं, चाहे वह रोड कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हों, या शिपिंग प्रोजेक्ट्स या फिर इन्फ्रास्ट्रक्चर की अन्य परियोजनाएं। उन्होंने कहा कि गोवा में नए एयरपोर्ट का जो काम शुरू हो रहा है, उससे निश्चित रूप से गोवा के अर्थतंत्र की प्राण टूरिज्म में भी कई गुना वृद्धि होगी।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह से गोवा का भाजपा संगठन श्री विनय तेंदुलकर के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार के साथ-साथ राज्य का पार्टी संगठन भी एक आदर्श संगठन के रूप में प्रतिष्ठित होगा। उन्होंने कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर गोवा भाजपा और विशेषकर दक्षिणी जिला भाजपा कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। ■

'तीन सालों में हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा पाये'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने पुदुच्चेरी के होटल आनंदा इन में 26 जून को आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धियों व मोदी सरकार द्वारा पुदुच्चेरी के विकास के लिए किये जा रहे कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। ज्ञात हो कि श्री शाह देश के सभी राज्यों में कुल 110 दिनों के अपने विस्तृत प्रवास कार्यक्रम के तहत अभी पुदुच्चेरी में हैं। इससे पहले श्री शाह ने पुदुच्चेरी पहुंचने पर महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, पत्रकार और महाकवि श्री सुब्रह्मण्य भारती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद श्री शाह ने JIPMER गेस्ट हाउस में प्रदेश कोर कमिटी की बैठक की। तत्पश्चात् उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चा अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों व जिला महासचिवों के साथ बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की। श्री शाह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मशती वर्ष कार्य विस्तारक योजना के तहत पुदुच्चेरी में बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक भी की।

श्री शाह ने कहा कि अभी हाल ही में मोदी सरकार ने कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे किये हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कार्य-संस्कृति रही है कि हम जब सत्ता में आते हैं तो हम जनादेश

का सम्मान करते हुए हर वर्ष अपने कामकाज का हिसाब देश की जनता के सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि जब श्री नरेन्द्र मोदी ने देश की कमान संभाली तो देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति दयनीय थी, लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से विकास करने वाली भरोसेमंद अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि शेयर बाजार आजादी के बाद के अपने सर्वोच्च शिखर पर है, महंगाई दर कम हुई है, केन्द्रीय अनुदान में राज्यों की हिस्सेदारी काफी बढ़ी है और फिस्कल डेफिसिट को तीन प्रतिशत तक लाने में हम सफल हुए हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कई सरकारें पचास-पचास वर्षों में एक-दो काम करती हैं जबकि नरेन्द्र मोदी सरकार ने तीन साल में ही ऐसे कई सारे काम किये हैं जो 50 सालों में कभी-कभार ही होते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस-नीत यूपीए की घपले-घोटाले और भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड वाली सरकार की जगह श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज एक ऐसी सरकार काम कर रही है जिस पर तीन सालों में हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा पाये। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमने पॉलिसी पैरालिसिस से ग्रस्त यूपीए सरकार की जगह एक निर्णायक और संवेदनशील सरकार देने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के तीन साल में 28 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक अकाउंट खोल कर देश के गरीबों को देश के अर्थतंत्र की मुख्यधारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल बाद देश में लगभग साढ़े 12 करोड़ लोगों के पास ही गैस सिलिंडर थे, जिसमें से लगभग 11 करोड़ 80 लाख गैस सिलिंडर केवल शहरी क्षेत्रों में थे। मोदी सरकार ने तीन साल में ही देश के सवा दो करोड़ गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन देने का काम पूरा कर लिया है। पांच सालों में देश के पांच करोड़ गरीब महिलाओं के परिवार में गैस कनेक्शन पहुंचाने का बीड़ा मोदी सरकार ने उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गैस सिलिंडर पहुंचाकर गरीब माताओं को धुएं से मुक्त करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मुद्रा बैंक के माध्यम से देश के लगभग 7.64 करोड़ लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराये गए हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी देश में लगभग 8 करोड़ घर ऐसे थे, जहां शौचालय नहीं थे, मोदी सरकार के तीन वर्ष में ही साढ़े चार करोड़ से ज्यादा शौचालय बना कर गांव की गरीब महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया गया है।

श्री शाह ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से भारत ने दुनिया भर में देश की सुरक्षा के प्रति सजग और एक मजबूत इच्छाशक्ति वाले राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि 40 वर्षों से लंबित 'OROP' को एक साल में लागू कर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के प्रति सम्मान और अपनी संवेदना को प्रकट करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में एक साथ 104 उपग्रह को स्थापित करके हम अंतरिक्ष विकास के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर बन कर उभरे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश की धरोहर और सांस्कृतिक विरासत योग को दुनिया भर में प्रतिष्ठित करने का काम किया है और आज दुनिया में 170 से अधिक देश तीन साल से 21 जून को योग

दिवस मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेरिस समझौते में पर्यावरण को बचाने की हमारी प्रतिबद्धता ने हमें दुनिया को नई दिशा दिखाने वाले देश के रूप में प्रतिष्ठित किया है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 1955 से काका साहब कालेलकर कमीशन से लंबित पिछड़े आयोग को संवैधानिक मान्यता देकर नरेन्द्र मोदी सरकार ने देश के पिछड़े वर्ग के लोगों को समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी देश में लगभग 18 हजार गांव ऐसे थे, जहां पर बिजली नहीं पहुंची थी। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से अब तक 13,900 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर लिया गया है और मई, 2018 तक देश में एक भी ऐसा गांव नहीं होगा, जहां

बिजली न पहुंची हो। उन्होंने कहा कि जेनरिक दवाओं के कांसेप्ट को व्यापक रूप में शुरू कर के मोदी सरकार ने गरीबों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जेनरिक दवाओं के कांसेप्ट से दवाओं के दाम 40% से लेकर 300% तक कम हुए हैं। उन्होंने कहा कि स्टेंट के मूल्य को 80% तक कम कर दिए जाने से दिल के मरीजों को काफी लाभ पहुंचा है।

श्री शाह ने कहा कि काले-धन के दुष्प्रभाव को देश की अर्थव्यवस्था से ख़त्म करने के लिए मोदी सरकार ने कई कदम उठाये हैं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का सफल और साहसिक कदम उठाकर देश की अर्थव्यवस्था को पारदर्शी बनाने में सरकार सफल हुई है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक चंदों को 2000 कैश तक सीमित करके राजनीतिक पार्टियों की चंदे की प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाने की पहल की गई है। उन्होंने कहा कि चाहे बेनामी संपत्ति पर क़ानून की बात हो, शत्रु संपत्ति बिल को पारित कराने की बात हो या फिर शेल कंपनियों के खिलाफ मुहिम की बात - केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हर मोर्चे पर अपनी दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए इन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि साइप्रस, सिंगापुर और मॉरीशस के रूट से जो काला-धन देश में आता था, उसे बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस सबका परिणाम है कि एक ही साल में लगभग 91 लाख नए पैन कार्ड रजिस्टर हुए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर के कलेक्शन में भी एक ही साल में लगभग 19% की बढ़ोतरी हुई है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने तीन साल में 106 लोक-कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत कर देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, आदिवासी, युवा एवं महिलाओं के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन की आधारशिला रखी है।

श्री शाह ने कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पुदुच्चेरी के विकास के लिए कई योजनओं का सूत्रपात किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पुदुच्चेरी को स्मार्ट सिटी की सौगात देने का काम किया है, लगभग 1850 करोड़ रुपये की लागत से पुदुच्चेरी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के तीन वर्षों में पुदुच्चेरी में 2,516 टॉयलेट्स का निर्माण किया गया है, लगभग 1.25 लाख जन-धन एकाउंट खोले गए हैं, मुद्रा बैंक योजना के जरिये राज्य के लगभग 2.45 लाख लोगों को लगभग 939 करोड़ रुपये का ऋण स्वरोजगार के लिए उपलब्ध कराया गया है। साढ़े 6 लाख एलईडी बल्ब बांटे गए हैं और गरीब माताओं को लगभग 805 गैस कनेक्शन अकेले पुदुच्चेरी शहर में उपलब्ध कराये गए हैं। उन्होंने कहा कि पुदुच्चेरी में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की सहायता से 161 करोड़ रुपये की लागत से गरीबों के लिए लगभग 65,000 आवास निर्माण का कार्य प्रगति पर है। साथ ही, अमृत योजना के तहत अर्बन डेवलपमेंट के लिए पुदुच्चेरी को अलग से लगभग 130 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गए हैं। उन्होंने कहा कि उदय योजना के तहत राज्य को इलेक्ट्रिफिकेशन के अपग्रेडेशन के लिए 400 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री वी नारायणसामी जब केंद्र की यूपीए सरकार में मंत्री थे, तब यूपीए के अंतिम तीन सालों की तुलना यदि मोदी सरकार के तीन साल से की जाय, तो मोदी सरकार ने पुदुच्चेरी को यूपीए की तुलना में लगभग 613% ज्यादा अनुदान दिया है।

राज्य की कांग्रेस सरकार कड़ा प्रहार करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यद्यपि मैं पुदुच्चेरी की नारायणसामी सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी भ्रष्ट सरकार कभी नहीं देखी। ■

भारत में ऐतिहासिक 'जीएसटी' की शुरुआत

संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित ऐतिहासिक मध्य रात्रि सत्र के बीच 30 जून की मध्य रात्रि से वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था लागू हो गई। राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री द्वारा बटन दबाकर देश में जीएसटी की शुरुआत करने से पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने सभा को संबोधित किया।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिन देश का भविष्य निर्धारित करने के लिहाज से एक निर्णायक मोड़ है। उन्होंने याद किया कि संसद का यह केंद्रीय कक्ष पहले भी कई ऐतिहासिक अवसरों का साक्षी रहा है जिसमें संविधान सभा का पहला सत्र, भारत की आजादी और संविधान को अंगीकार करना शामिल हैं। उन्होंने जीएसटी को सहकारी संघवाद का एक उदाहरण बताया।

उन्होंने चाणक्य का उल्लेख करते हुए कहा कि कड़ी मेहनत सभी बाधाओं को दूर कर सकती है और यह हमें सबसे कठिन उद्देश्यों को पूरा करने में भी मदद करती है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सरदार पटेल ने देश का राजनीतिक एकीकरण सुनिश्चित किया था, उसी तरह जीएसटी आर्थिक एकीकरण सुनिश्चित करेगा। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने कहा था कि आयकर दुनिया में समझने के लिए सबसे मुश्किल चीज है, को याद करते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी एक राष्ट्र-एक कर सुनिश्चित करेगा।

उन्होंने कहा कि जीएसटी से समय और लागत में काफी बचत होगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की सीमाओं को पार करते समय होने वाली देरी से जलने वाले इंधन की अब बचत होगी और इससे पर्यावरण को भी फायदा पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी एक आधुनिक कर प्रशासन को बढ़ावा देगा जो अपेक्षाकृत आसान एवं अधिक पारदर्शी होगा और इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। उन्होंने जीएसटी को 'गुड एंड सिम्पल टैक्स' यानी अच्छा एवं आसान कर कहा जिससे अंतत: लोगों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने समाज के पारस्परिक एवं सांझा लाभ के लिए साझा लक्ष्य और समान दृढ संकल्प की भावना का वर्णन करने के लिए ऋग्वेद के श्लोक का भी उल्लेख किया।

'वस्तु एवं सेवा कर': एक तथ्य

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक ऐतिहासिक कर सुधार है, जो 1 जुलाई, 2017 से लागू हो गया। जीएसटी देश में परोक्ष कराधान परिदृश्य को पूरी तरह बदल देगा, जिसमें केन्द्र और राज्य दोनों के कर शामिल है। सामान्य पद्धति से भिन्न, जीएसटी का संचालन केन्द्र और राज्यों द्वारा एक साथ किया जाएगा।

जीएसटी क्यों महत्वपूर्ण है

जीएसटी स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा कर सुधार है। यह 'एक राष्ट्र - एक कर – एक बाजार' का लक्ष्य हासिल करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। जीएसटी से सभी पक्षों को लाभ पहुंचेगा, जैसे उद्योग, सरकार और उपभोक्ता। इससे वस्तुओं और सेवाओं की लागत में कमी आएगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और उत्पाद एवं सेवाओं को वैश्विक रूप में प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सकेगा और 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को मुख्य रूप से बल मिलेगा। जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत, निर्यात पर कर की दर शून्य हो जाएगी, जो वर्तमान प्रणाली से एक दम भिन्न होगी। चूंकि वर्तमान में कुछ करों का रिफंड इसलिए नहीं हो पाता है, क्योंकि परोक्ष करों का स्वरूप केन्द्र और राज्यों के बीच विखंडित है। जीएसटी भारत को एक साझा बाजार बनाएगा, जिसमें करों की दरें और प्रक्रियाएं एक समान होंगी तथा आर्थिक अड़चनें समाप्त हो जाएंगी। जीएसटी अधिकतर प्रौद्योगिकी संचालित होगा और इससे मानव सम्पर्क बहुत कम होगा।

जीएसटी से भारत में व्यापार करने की प्रक्रिया आसान होने की संभावनाएं है। वस्तुओं की अधिसंख्य आपूर्तियों में जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित कर की दर वर्तमान में केन्द्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से लगाए जाने वाले करों (जैसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दरें/सन्निहित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दरें/क्लीयरेंस-परवर्ती सन्निहित सेवा कर, वैट दरें या भारित औसत वैट दरें, उत्पाद शुल्क पर वैट का प्रपाती प्रभाव, केन्द्रीय बिक्री कर, चुंगी कर, प्रवेश कर आदि के कारण लगने वाले टैक्स) की दरों से काफी कम होगी।

संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के बाद जीएसटी की यात्रा

8 सितम्बर, 2016 को माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 अस्तित्व में आया। जीएसटी परिषद की स्थापना 15.09.2016 को की गई।

सितम्बर, 2016 में अपनी स्थापना के बाद से जीएसटी परिषद की 18 बैठकें हो चुकी हैं। व्यापक बैठकों में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों अथवा उनके प्रतिनिधियों तथा केन्द्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया और इस ऐतिहासिक कर सुधार को लागू करने के लिए विधि एवं प्रक्रिया तैयार की। यह एक विशाल कार्य था, जिसमें 27,000 से भी ज्यादा कार्य घंटों का समय लगा। जीएसटी के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए केन्द्र और राज्यों के अधिकारियों ने देश के विभिन्न भागों में 200 से अधिक बैठकों में हिस्सा लिया।

29 मार्च, 2017 को माननीय वित्त मंत्री ने लोकसभा में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित चार विधेयक लोकसभा के विचारार्थ एवं पारित करने हेतु पेश किये। ये थे- केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) विधेयक, 2017, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) विधेयक, 2017, संघ शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) विधेयक, 2017 और जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) विधेयक, 2017। ये सभी विधेयक लोक सभा ने 29 मार्च, 2017 को और राज्य सभा ने 06 अप्रैल, 2017 को पारित कर दिये।

जीएसटी भारत को एक साझा बाजार बनाएगा, जिसमें करों की दरें और प्रक्रियाएं एक समान होंगी तथा आर्थिक अड़चनें समाप्त हो जाएंगी। जीएसटी अधिकतर प्रौद्योगिकी संचालित होगा और इससे मानव सम्पर्क बहुत कम होगा।

जीएसटी परिषद ने जीएसटी के अंतिम ढांचे को निम्नांकित रूप में मंजूर किया है:

- विशेष श्रेणी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के लिए जीएसटी लगाने से छूट की सीमा 20 लाख रुपये होगी, विशेष श्रेणी राज्यों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये होगी।
- जीएसटी के लिए 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की चार स्लैब टैक्स दर संरचना का अनुमोदन किया गया है।
- कुछ वस्तुओं पर एक उपकर लगाया जाएगा, जिनमें लक्जरी कारें,

वातित पेय पदार्थ, पान मसाला और तम्बाकू उत्पाद शामिल है, जिन पर जीएसटी की 28 प्रतिशत की दर के ऊपर उप कर लगाया जाएगा, ताकि राज्यों को प्रतिपूरक भुगतान किया जा सकें।

- विशेष श्रेणी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के लिए कम्पोजिशन स्कीम का लाभ उठाने की सीमा 75 लाख रूपये होगी, जबकि विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 50 लाख रूपये होगी और उन्हें केवल तिमाही रिटर्न दाखिल करनी होगी, सेवा प्रदात्ताओं की कुछ श्रेणियों (रेस्टोरेंट को छोडकर) को कम्पोजिशन स्कीम से बाहर रखा गया है।

जीएसटी की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं

- जीएसटी में सभी लेन देन और प्रक्रियाएं केवल इलेक्ट्रोनिक मोड के जरिये की जाएगी, ताकि हस्तक्षेप रहित प्रशासन का लक्ष्य हासिल किया जा सकें। इससे करदाताओं को कर अधिकारियों के साथ कम से कम भौतिक सम्पर्क करना होगा।
- जीएसटी में मासिक रिटर्न और वार्षिक रिटर्न के स्वतः-सृजन सुविधा का प्रावधान है।
- इसमें करदाताओं को 60 दिन के भीतर निर्धारित अनुदान का रिफंड प्रदान करने और सात दिन के भीतर निर्यातकों को 90 प्रतिशत रिफंड अस्थायी रूप से जारी करने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। समय पर रिफंड मंजूर न होने की स्थिति में ब्याज भुगतान और रिफंड सीधे बैंक खातों में क्रेडिट करने जैसे उपाय भी किये गये है।

जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) की भूमिका– जीएसटी का आईटी आधार

जीएसटीएन का सृजन 25 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के सैक्शन के रूप में किया गया है, जिसका कार्यनीतिक नियंत्रण सरकार के पास होगा। यह नेटवर्क करदाताओं के लिए एक साझा पोर्टल के रूप में काम करेगा। इस साझा पोर्टल पर करदाता अपने पंजीकरण आवेदन, रिटर्न दाखिल करेंगे, कर का भुगतान करेंगे, रिफंड के दावे आदि करेंगे। जीएसटीएन के लिए एक मजबूत आईटी मंच प्रदान किया गया है, जो 80 लाख करदाताओं और हजारों कर अधिकारियों को इंटरफेस प्रदान करेगा। जीएसटी के अंतर्गत सभी प्रकार की फाइलिंग इलेक्ट्रोनिक ढंग से की जाएगी।

राज्य कर प्रशासनों पर केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के सभी मौजूदा करदाताओं का पंजीकरण जीएसटी प्रणाली में 8 नवम्बर, 2016 से शुरू हो गया था। 66 लाख से अधिक करदाताओं ने जीएसटी पोर्टल पर अपने खाते सक्रिय कर लिये है।

भुगतान से संबंधित जीएसटी एप्लीकेशन चालू हो गया है। 25 बैंकों को जीएसटी साझा पोर्टल के साथ जोड़ दिया है, जो एनईएफटी/आरटीजीएस और क्रेडिट/डेबिट कार्ड के जरिये लेनदेन की सुविधाए प्रदान करेंगे।

जीएसटी सम्पर्क कार्यक्रम

सरकार ने विभिन्न गतिविधियों, कार्यशालाओं, मीडिया और टेलीविजन के जरिये जन समुदायों से सम्पर्क कार्यक्रम तैयार किया है। सीबीईसी के क्षेत्रीय संगठनों को सभी स्तरों पर सक्रिय कर दिया गया है, ताकि जीएसटी में परिवर्तन के दौरान व्यापार और उद्योग की मदद की जा सके और उनके संदेह दूर किये जा सके। देश भर में कुल 4700 कार्यशालाएं आयोजित की गई।

प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया, आउटडोर होर्डिंग आदि के जरिये एक व्यापक मल्टी मीडिया अभियान चलाया गया, ताकि जीएसटी में सुचारू रूपांतरण के लिए करदाताओं और अन्य संबद्ध पक्षों को सूचना, शिक्षा और सहायता प्रदान की जा सकें।

सीबीईसी का पुनर्गठन

जीएसटी के कार्यान्वयन और संचालन के लिए केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) का पुनर्गठन अनिवार्य हो गया था। इसे देखते हुए बोर्ड में ढांचागत परिवर्तन किये गये और सक्षम कार्मिक तैनात किये गये। देश के सुदूरतम कोनों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निदेशालयों का विस्तार किया गया और मजबूत बनाया गया।

फील्ड संगठनों का पुनर्गठन करते हुए 21 सीजीएसटी और सीएक्स जोन, 107 सीजीएसटी और सीएक्स आयुक्त कार्यालय, 12 उपायुक्त कार्यालय, 768 सीजीएसटी और सीएक्स डिविजन, 3969 सीजीएसटी और सीएक्स रेंज और 48 लेखा परीक्षा आयुक्त कार्यालय और 49 अपील आयुक्त कार्यालय बनाये गये हैं।

प्रशिक्षण

जीएसटी के सुचारू रूप से संचालन के लिए पर्याप्त क्षमता निर्माण और जागरूकता आवश्यक है। इसके लिए नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नरकोटिक्स (एनएसीआईएन) ने व्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किये गये। पहले चरण के दौरान समूचे देश के करीब 52 हजार अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। अद्यतन कानून, नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी देने के लिए एक रीफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, इसमें 23 जून, 2017 तक 17,213 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

इसके अलावा जीएसटी के बारे में 500 एफएक्यू (बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न) अंग्रेजी, हिन्दी और 10 क्षेत्रीय भाषाओं में जारी किये गये है।

सोशल मीडिया के जरिये सेवा

जीएसटी से संबंधित सवालों का तत्काल आधार पर जवाब देने के लिए सरकार ने एक ट्वीटर सेवा शुरू की है। ट्वीटर हैण्डल askGST_GOI हर रोज हजारों करदाताओं के सवालों का जवाब दे रहा है। ट्वीटर पर बार-बार पूछे गये सवालों को प्रश्नोत्तरी के रूप में पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। ■

एकात्मता की चिर साधना

–दीनदयाल उपाध्याय

भारत की एकता और अखंडता की साधना हमने सदा से की है। हमारे राष्ट्र का इतिहास इस साधना का ही इतिहास है। 'पृथिव्या समुद्र पर्यन्ताया एक राष्ट्र' का उद्घोषण करने वाली ऋषियों की मंत्रपूत वाणी की पृष्ठभूमि में 'नील सिंधु जल धौत चरणातल' भारत की एकता का साक्षात्कार ही था। हिम किरीटिनी एवं सिंधुवलयांकित माता का दर्शन करके ही आदिकवि ने माता का गौरव बढ़ाने वाले सपूत मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की गुण गरिमा का बखान किया तो यही कहा ''समुद्र इव गाम्भीर्येण धैर्येणा हिमवानिव।'' हिमालय और समुद्र की मर्यादाएं ही राष्ट्रपुरुष राम के चरित्र की मर्यादाएं बन गईं। कुरुक्षेत्र की सीमाओं में आबद्ध महर्षि वेदव्यास का 'जय' काव्य जब तक महाभारत बनकर कैलास से कन्याकुमारी और गांधार से कामरूप तक विस्तीर्ण देश का दर्शन नहीं करा सका, वह हमारे जीवन का केंद्र नहीं बन पाया। अपने संपूर्ण जीवन का साक्षात्कार करने पर ही कवि ने गर्वोक्ति की 'यद्भारते तद्भारते यत्र भारते तत्र भारते।' कथन सत्य है, कारण महाभारत में जिस प्रदेश का वर्णन किया है, भारत का न्याय वहीं तक रहा है। कविकुल कमल दिवाकर कालिदास की कविता जब यक्ष के हृदय की वेदना को लेकर अवतीर्ण हुई, तो उसे रामगिरि से लेकर अलकापुरी तक भारत का गुण-गान किए बिना शांति नहीं मिली। रघुवंश की दिग्विजय के वर्णन में उन्होंने संपूर्ण देश का दिग्दर्शन करा दिया है। उनके हृदय की यह एकात्मानुभूति ही उन्हें महाकवि बना सकी। पुराणों में जिस भारत का वर्णन मिलता है, वह आसिंधु-सिंधुपर्यंत अखंड भारत ही है। वहां भारतवर्ष की व्याख्या इन शब्दों में की गई है-

उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम्।
वर्षम् तद्भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः।।

निश्चित ही उपर्युक्त व्याख्या संपूर्ण भारत का एकात्मक चित्र उत्पन्न कर देती है।

बार्हस्पत्य अर्थशास्त्र में 'भारतः खण्डः' सूत्र की अनुवृत्ति में आने वाले निम्न सूत्र जिस भारत के विस्तार का वर्णन करते हैं, वह अखंड भारत ही है।

सहस्रयोजना बदरिका-सेत्वन्ता।।
द्वारकादि-पुरुषोत्तम सालग्रामान्ता सप्तशतयोजना।।
तत्रापि रैवतक-विन्ध्य-सह्य-महेन्द्र-मलय-श्रीपर्वत-
परियात्रा सप्त कुलाचलाः।।
गंगा-सरस्वती-कालिन्दी-गोदावरी-कावेरी-
ताम्रपर्णी-कृतमालाः कुलनद्यश्च।।

अर्थात् बद्री-केदार से लेकर रामेश्वर तक 1000 योजन लंबा तथा द्वारका से लेकर पुरी तक 700 योजन चौड़ा देश भारतवर्ष है। रैवतकादि मुख्य 7 पर्वत तथा गंगा, सरस्वती आदि मुख्य 7 नदियां हैं।

भारत में उत्पन्न एवं प्रचलित सभी मतों और संप्रदायों के सम्मुख भी भारत की एकता का चित्र रहा है। उनके तीर्थ-स्थान भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक फैले हुए हैं। उनकी यात्रा करने वाला सहज ही भारत की परिक्रमा कर लेता है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ की वेदी में अपने शरीर की आहुति देने पर सती के शव को अपने कंधे पर डाले भगवान् शिव ने संपूर्ण भारत की यात्रा की। जहां-जहां सती के अंग गिरे, वहीं शक्ति का पीठ बन गया। दूसरे जन्म में भी सती ने पार्वती के रूप में 'कोटि जनम लौं रगर हमारी बरहुं शम्भु नतु रहहुं कुंआरी' की प्रतिज्ञा कर अपनी तपस्या के लिए हिमालय की गुफाएं अथवा कैलास का गिरिशृंग नहीं चुना, बल्कि भारत के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी को ही उपयुक्त समझा। कन्याकुमरी में स्थित कुमारी पार्वती की तपस्या तथा कैलासवासी भगवान् शिव की साधना से शिव-पार्वती का विवाह दक्षिण और उत्तर के मिलन की पवित्र भूमिका पर घटित आख्यायिका के रूप में सहज समझा जा सकता है।

सूर्य के 12 मंदिर, गाणपत्यों के अष्ट विनायक, शैवों के बारह ज्योतिर्लिंग, शाक्तों के 51 पीठ तथा वैष्णवों के अगणित तीर्थक्षेत्र संपूर्ण भारत में बिखरे पड़े हैं। बौद्ध, जैन, सिक्ख तथा विभिन्न संतों के आचार्य मानकर चलने वाले छोटे-मोटे पंथ भी एकदेशीय न होकर सर्वदेशीय दृष्टिकोण लेकर चलते हैं तथा भारत का कण-कण उनके लिए वंदनीय है। भगवान् शंकराचार्य ने तो सभी मतों का समन्वय करते हुए भारत के चारों कोनों पर ऐसे चार क्षेत्रों का विधान किया, जो सबके लिए समान रूप से पूज्य बन गए। हिमाचल के हिमाच्छादित शिखर पर अवस्थित बद्रीनाथ की यात्रा सब प्रांतों और संप्रदायों के लोगों के जीवन की कामना रही है। महोदधि और रत्नाकर दोनों ही जहां माता के चरणों का प्रक्षालन करते हैं, वहां भारत के कोने-कोने से जाकर नित्य प्रति भक्तगण श्री रामेश्वरम् के शिवलिंग पर गंगोत्तरी का जल चढ़ा उत्तर-दक्षिण की एकता के अजस्र स्रोत में अवगाहन करते हुए 'शिव' की आराधना करते हैं। 'जगन्नाथ का भात, पूछो जात न पांत' कहकर जिस प्रेम और श्रद्धा से श्रीजगन्नाथ जी का प्रसाद पाते हैं, वह तो राष्ट्रीय संगठन के लिए संजीवनी काम करता रहा है। प्रोग्ज्योतिष के सम्राट् नरकासुर का वध करके 16000 राजकुमारियों को मुक्त करने वाले भगवान् वासुदेव कृष्ण की राजधानी द्वारकापुरी

भी हमारे प्रमुख तीर्थों में से हैं। इसी प्रकार पुराणकारों ने जब कहा-

अयोध्या मथुरा माया काशी कांचि अवन्तिका।

पुरा द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः।।

तब वे भारतीय अखंडता का ही विधान कर रहे थे। ये सातों पुरियां भारतीय राष्ट्र के मर्मस्थल, उसकी सभ्यता और संस्कृति की केन्द्र हैं। एक-एक के साथ अतीत की इतनी घटनाओं का संबंध है कि उनकी स्मृतिमात्र से अपना संपूर्ण इतिहास चलचित्र की भांति आंखों से गुजर जाता है।

भारतीय एकता का साक्षात्कार कराने के लिए तीर्थ-यात्राओं का ही नहीं, अपितु अन्य और भी विधान किए गए। अनेक छोटे-मोटे मेलों के अतिरिक्त हरिद्वार, प्रयाग, उज्जयिनी और नासिक इन चार प्रमुख स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है, जिसमें भारत के कोने-कोने से साधु, संत और यात्री आते हैं। इन्हें एक प्रकार का राष्ट्रीय सम्मेलन कहा जा सकता है, जहां भारत की अखंडता राष्ट्रीयता का दर्शन होता है और यह अवसर प्रति तीसरे वर्ष आता है। हमारे दैनिक आचरण में भी राष्ट्रीयता के पोषक संस्कारों का समावेश किया गया है। प्रातः उठकर भूमि पर चरण रखते ही अत्यंत विनीत भाव से हिंदू पृथ्वी माता को नमस्कार करता हुआ कहता है-

समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले।

विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे।।

वहीं संपूर्ण भारत का चित्र है। प्रातः स्मरण में जिन महापुरुषों का पुण्य स्मरण किया जाता है वे भारत के किसी प्रांत-विशेष के नहीं अपितु संपूर्ण भारत के हैं। स्नान के समय जब जल को अभिमंत्रित करते हैं तो

गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति।

नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु।।

के मंत्र से भारत की सभी पवित्र नदियों का आह्वान करते हैं। इन नदियों के समान ही 7 वन, 7 पर्वत और 4 सरोवरों को, जो संपूर्ण भारत में फैले हुए हैं, अपने अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया है।

हमारे नीतिकार एवं शास्त्रकार भी संपूर्ण भारत की एकता का अनुभव करके ही शास्त्रों की रचना करते रहे हैं। हमारे जीवन में बाह्य भिन्नताएं चाहे कितनी ही दिखती हों, किंतु हमारी जीवन की दृष्टि एक ही है। यह दृष्टिकोण की एकता समान संस्कारों से उत्पन्न हुई है। गर्भाधान से लेकर दाह संस्कार तक सभी संस्कार सब हिंदुओं के लिए समान रूप से निहित हैं। गंगोदक सभी के लिए मोक्षदाता है एवं मृत्यु के पश्चात् हमारी अस्थियां गंगाजी में ही विसर्जित की जाती हैं। हिंदूमात्र के संस्कार होते हैं। संख्या और संकल्प में हम सदैव संपूर्ण भारतभूमि का ध्यान करते हैं।

मनु से लेकर बृहस्पति तक बनाई हुई स्मृतियों में किसी विशेष प्रदेश के अथवा विशेष वर्ग के व्यक्तियों के जीवन संबंध में विधान नहीं है अपितु सभी भारतीयों के संबंध में समान नियमों का आदेश है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्यपर्यंत सभी विद्वानों ने संपूर्ण भारत की एकता का विचार करते हुए एकसूत्रीय शासन का विधान किया है। आयुर्वेद ने 'यस्य देशस्य यो जन्तुः तज्जं तस्यौषधिः' के सिद्धांत का ध्यान में रखते हुए भारत के निवासियों, उनके रोग एवं भारत की वनस्पतियों का विचार किया है। भारत बाह्य किसी भी देश के रोग और वनस्पतियों का न तो उसमें विचार है और न देशांतर्गत किसी प्रदेश की वनस्पतियों को उसमें छोड़ा गया है। भूमि-व्यवस्था, ग्राम पंचायतें और श्रेणी संपूर्ण देश में एक ही रूप में चलते थे। यातायात के लिए विभिन्न स्वरूप के अनेक वाहन होते हुए भी सिंधु और बंगाल, कश्मीर और केरल सभी प्रांतों में प्रयुक्त वाहनों के धुरों की लंबाई एक ही चली आ रही है। राजस्व की व्यवस्था भी संपूर्ण भारत में एक ही रही है।

भारतीय एकता की आराधना हमारी राजनीति का भी विषय रही है। संपूर्ण भारत को एक शासन-सूत्र में बांधकर चातुरंत साम्राज्य निर्माण करने की अभिलाषा हमारे यहां के राजाओं की अत्यंत पवित्र महत्वाकांक्षा रही है। राजाओं के संधि, विग्रह और अभियान सबका उद्देश्य भारत की एक-सूत्रता की रक्षा ही रहा है। 'अश्वमेध' और 'राजसूय' यज्ञों से इसी उद्देश्य की सिद्धि हुई है। रघु की दिग्विजय से जो एकछत्र साम्राज्य निर्माण हुआ, उसके शिथिल हो जाने पर ही भगवान् राम का अवतार हुआ। उनका अवतार कार्य उत्तर और दक्षिण के सभी प्रदेशों को एक शासन-सूत्र में गूंथकर पूर्ण हुआ। अश्वमेध यज्ञ भगवान् राम के कार्यों में सुमेरु के समान है। भगवान् कृष्ण ने भी धर्मराज युधिष्ठिर की अध्यक्षता में जिस चातुरंत साम्राज्य का निर्माण किया, वह भारत की अंखडता को बनाए रखने का महान् प्रयत्न था। भारत के पश्चिमोत्तर द्वार को जैसे ही सिकंदर ने खटखटाया, वैसे ही आचार्य चाणक्य ने 'न त्वेवार्यस्य दासभावः' की घोषणा की तथा चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी को ही खदेड़कर बाहर ही नहीं किया, अपितु छोटे-मोटे गणराज्यों को समाप्त कर एक सुदृढ़ एवं शक्तिशाली साम्राज्य की नींव भी डाली। भारत की एकता का यह प्रबल प्रमाण है कि जब-जब उत्तर में विदेशियों का आघात हुआ, तो केवल उत्तर को ही नहीं, दक्षिण को भी मर्मांतक पीड़ा पहुंची। सिर पर चोट लगते ही जैसे संपूर्ण शरीर की शक्तियां प्रतिकार करने को उद्यत हो जाती हैं, उसी प्रकार शकों और हूणों के आक्रमण का प्रतिरोध दक्षिण से उठने वाली शकारि विक्रमादित्य और यशोधर्मन की शक्तियों ने किया। मुगलों के साम्राज्य को मिटाने का सत्संकल्प दक्षिण में छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। आधुनिक युग के राजनीतिक नेताओं के नामोउल्लेख की आवश्यकता नहीं; उनका कार्यक्षेत्र भी अखिल भारतीय ही रहा। इस प्रकार सुख और दुःख जय और पराजय, वैभव और पराभ्पव में जो एकता और अभिन्नता प्रकट की गई, उसने हमारे राष्ट्र को एक जीवन के अछेद्य सूत्र में संगठित किया है।

जीवन के सभी क्षेत्रों में प्राप्त एकता का अनुभूति-क्षेत्र केवल भौतिक जगत् तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि हमारी आध्यात्मिक चेता को भी व्याप्त कर गया। हमारे देश, राष्ट्र एवं संस्कृति की एकता हमारी आत्मा के समान ही चैतन्ययुक्त है। इस आत्मा को खंडित नहीं किया जा सकता। ■

(साभार: दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय खंड १)

बाल गंगाधर तिलक

(23 जुलाई 1856- 1 अगस्त, 1920)

बाल गंगाधर तिलक विद्वान, गणितज्ञ, दार्शनिक और प्रखर राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की नींव रखने में सहायता की। तिलक ने सन् 1914 ई. में 'इंडियन होमरूल लीग' की स्थापना की और इसके अध्यक्ष रहे।

जीवन परिचय

बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई, सन् 1856 ई. को महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में हुआ था। इनका पूरा नाम 'लोकमान्य श्री बाल गंगाधर तिलक' था। उन्होंने सन् 1876 ई. में बी.ए. आनर्स की परीक्षा पास की और सन् 1879 ई. में बंबई विश्वविद्यालय से एल.एल.बी. किया। शिक्षा के बाद तिलक ने अपना अधिकांश समय सार्वजनिक सेवा में लगाने का निश्चय किया।

स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सेदारी

तिलक सन् 1905 ई. से सक्रिय राजनीतिक आंदोलन में पूरी तरह कूद गए। बंगाल के विभाजन के कारण देश में राष्ट्रवादी भावनाओं का ज्वार आया। इसी के साथ स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा आदि स्वराज्य जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के लिए तिलक के विचार ज्यादा प्रखर थे। नरम दल के लोग छोटे सुधारों के लिए सरकार के पास वफ़ादार प्रतिनिधिमंडल भेजने में विश्वास रखते थे। वहीं, तिलक का लक्ष्य स्वराज था, छोटे- मोटे सुधार नहीं और उन्होंने कांग्रेस को अपने प्रखर विचारों को स्वीकार करने के लिए राज़ी करने का प्रयास किया।

इस मामले पर सन् 1907 ई. में कांग्रेस के 'सूरत अधिवेशन' में नरम दल के साथ उनका संघर्ष हुआ। अंग्रेजों की सरकार ने तिलक पर राजद्रोह और आतंकवाद फ़ैलाने का आरोप लगाकर उन्हें छह वर्ष के कारावास की सज़ा दे दी और मांडले (बर्मा) वर्तमान म्यांमार में निर्वासित कर दिया। 'मांडले जेल' में तिलक ने अपनी महान कृति 'भगवद्गीता -रहस्य' का लेखन शुरू किया, जो हिन्दुओं की सबसे पवित्र पुस्तक का मूल टीका है। तिलक ने भगवद्गीता के इस रूढ़िवादी सार को ख़ारिज कर दिया कि यह पुस्तक संन्यास की शिक्षा देती है। उनके अनुसार, गीता से मानवता के प्रति निःस्वार्थ सेवा का संदेश मिलता है।

इंडियन होमरूल लीग की स्थापना

प्रथम विश्वयुद्ध के ठीक पहले सन् 1914 ई. में रिहा होने पर वह पुनः राजनीति में कूद पड़े और 'स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा' के नारे के साथ इंडियन होमरूल लीग की स्थापना की। सन् 1916 ई. में वह फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए तथा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए। 'इंडियन होमरूल लीग' के अध्यक्ष के रूप में तिलक सन् 1918 में इंग्लैंड गए। गौरतलब है कि तिलक पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने कहा था कि भारतीयों को विदेशी शासन के साथ सहयोग नहीं करना चाहिए।

सामाजिक और राजनीतिक दर्शन

पुरानी परंपरा और संस्थाओं के प्रति जनता में अब नई जागरूकता प्रकट हो रही थी। इसके सबसे स्पष्ट उदाहरण थे पुरानी धार्मिक आराधना, गणपति-पूजन और शिवाजी के जीवन से जुड़े प्रसंगों पर महोत्सवों का आयोजन। इन दोनों आंदोलनों के साथ तिलक का नाम घनिष्ठ रूप से जुड़ा। तिलक का दृढ़ विश्वास था कि पुराने देवताओं और राष्ट्रीय नेताओं की स्वस्थ वंदना से लोगों में सच्ची राष्ट्रीयता और देशप्रेम की भावना विकसित होगी। विदेशी विचारों और प्रथाओं के अंधानुकरण से नई पीढ़ी में अधार्मिकता पैदा हो रही है और उसका विनाशक प्रभाव भारतीय युवकों के चरित्र पर पड़ रहा है। तिलक का विश्वास था कि अगर स्थिति को इसी प्रकार बिगड़ने दिया गया तो अंततः नैतिक दिवालिएपन की स्थिति आ जाएगी, जिससे कोई भी राष्ट्र उबर नहीं सकता। तिलक के विचार में, भारतीय युवकों को स्वावलंबी और अधिक ऊर्जावान बनाने के लिए उनको अधिक आत्म-सम्मान का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

तिलक मौलिक विचारों के व्यक्ति थे। वह संघर्षशील और परिश्रमशील भी थे। वह विशेष प्रसन्नता का अनुभव तब करते थे, जब उन्हें कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। उनके कार्य परोपकार की भावना से भरे होते थे। उनकी एकमात्र इच्छा लोगों की भलाई के लिए कार्य करना था। उनमें योग्यता, अध्यवसाय, उद्यमशीलता और देश-प्रेम का ऐसा अनूठा संगम था कि अंग्रेज़ सरकार उनसे हमेशा आशंकित रहती थी। 1 अगस्त, सन् 1920 ई. में बंबई में तिलक की मृत्यु हो गई। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा। ■

प्रधानमंत्री की पुर्तगाल, अमेरिका और नीदरलैंड की सफल यात्रा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 जून से 27 जून तक पुर्तगाल, अमेरिका और नीदरलैंड की सफल यात्रा की। इस यात्रा से इन देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिला। साथ ही अंतरिक्ष से लेकर आतंकवाद तक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाएं व समझौते हुए।

पुर्तगाल

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की लिस्बन यात्रा के दौरान 24 जून को दोनों पक्षों ने भारत-पुर्तगाल अंतरिक्ष एलायंस बनाने और मिलकर अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता पुर्तगाल के साथ भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साझेदारी को अजोरस द्वीपसमूह-अटलांटिक इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर-पर एक अद्वितीय केंद्र की स्थापना के लिए बढ़ावा देगा।

यह केंद्र, ट्रांस अटलांटिक एव उत्तर-दक्षिण सहयोग के लिए एक अनुसंधान, नवाचार (इनोवेशन) और नॉलेज (ज्ञान) हब के तौर पर काम करेगा। अनुसंधान एवं शैक्षिक संगठनों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क बनाया जाएगा। इसका लक्ष्य अनुसंधान के लिए एक साझा वातावरण तैयार करना और नई जलवायु, पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं समुद्री शोध को बढ़ावा देना है। इसमें अंतरिक्ष के संबंध में सहयोग की उम्मीद है, जिसमें अगली पीढ़ी के नैनो एवं माइक्रो उपग्रहों का विकास और आपसी सहयोग शामिल है।

पुर्तगाल 40 लाख यूरो का संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कोष बनाने पर सहमत

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम दो ऐसे देश हैं जिनका गहरा ऐतिहासिक जुड़ाव और मजबूत आर्थिक एवं जन संपर्क रहा है। इसलिए, मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने अब तक पुर्तगाल की द्विपक्षीय यात्रा नहीं की। हालांकि, मैं इस तथ्य से संतुष्ट हूं कि छह महीने के अंदर भारत और पुर्तगाल के बीच यह दूसरी वार्ता है।

श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री कोस्टा और मैंने आज व्यापक विचार-विमर्श किया और उनकी भारत की ऐतिहासिक यात्रा के बाद से हासिल प्रगति की समीक्षा की। हमारे संबंधों का ऊपर की तरफ बढ़ना जारी है। पिछले वर्ष द्विपक्षीय व्यापार 17 प्रतिशत बढ़ा है और पुर्तगाल से भारत में आने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भले की कम हो, लेकिन 2016-17 में यह दोगुना हो गया है। दो अर्थव्यवस्थाओं के बीच ऐसा बहुत कुछ है जो हम माल, सेवाओं, पूंजी और मानव संसाधन के प्रवाह को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। इस संबंध में, पुर्तगाल में आर्थिक बदलाव और भारत का सुदृढ़ विकास हमारे लिए एक साथ आगे बढ़ने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारा सहयोग गति पकड़ रहा है। अत्याधुनिक तकनीक के क्षेत्र में सहयोग के लिए हम 40 लाख यूरो का संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कोष बनाने पर सहमत हुए हैं। हम नैनो तकनीक, समुद्री विज्ञान एवं ओशियेनोग्राफी के क्षेत्र में पुर्गताल की विशेषज्ञता से सीखने के लिए उत्सुक हैं। अंतरिक्ष हमारे द्विपक्षीय सहयोग का नया क्षेत्र है। यह आइडिया प्रधानमंत्री कोस्टा की इस वर्ष की शुरुआत में भारत यात्रा के दौरान सामने आया। हमें पुर्तगाल के साथ अटलांटिक इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर में काम करने का इंतजार है। इसमें अंतरिक्ष और समुद्री विज्ञान दोनों क्षेत्र आते हैं।

आतंकवाद पर भारत–अमेरिका एक साथ

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 जून अमेरिका में रहे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबधों को और मजबूत बनाने तथा आतंकवाद

को मिलकर खत्म करने की बात पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साझा बयान में दोनों देशों के कारोबारी रिश्ते बेहतर करने और नौकरियों के मौके बढ़ाने पर जोर दिया गया। जहां श्री ट्रंप ने भारत को अमेरिका का सच्चा दोस्त बताया, वहीं श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा में अमेरिका के साझेदार होने की बात कही। साथ ही भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान से यह सुनिश्चित करने को कहा कि उसकी धरती का इस्तेमाल सीमा पार आतंकी हमलों के लिए न हो।

अपने प्रेस वक्तव्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी यह यात्रा तथा मेरी और आपकी आज की वार्ता हमारे दोनों देशों की सहयोग के इतिहास में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण पृष्ठ होगा। श्री मोदी ने कहा मेरी आज की बातचीत हर प्रकार से अत्यंत महत्वपूर्ण रही। ऐसा इसलिए, क्योंकि यह परस्पर विश्वास पर आधारित थी; क्योंकि इस के मध्य नज़र ये हमारे मूल्य, प्राथमिकताएं, चिन्ताएं और रूचियों की समानता; क्योंकि यह भारत तथा अमेरिका के बीच परस्पर सहयोग तथा सहभागिता की चरम सीमाओं की उपलब्धि पर केन्द्रित है; क्योंकि हम दोनों ग्लोबल इंजिन्स ऑफ़ ग्रोथ हैं; क्योंकि दोनों देशों तथा समाजों का चौमुखी आर्थिक विकास तथा इन की सांझी प्रगति राष्ट्रपति जी का तथा मेरा मुख्य लक्ष्य था और आगे भी रहेगा; क्योंकि आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतिया से अपने समाजों की सुरक्षा राष्ट्रपति ट्रंप तथा मेरी सर्वोत्तम प्राथमिकताओं मे से एक है।

प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कंपनी प्रमुखों से की मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 25 जून को वाशिंटन डीसी में आयोजित राउंड टेबुल बैठक में अमेरिका की शीर्ष बीस कंपनियों के प्रमुखों के साथ मुलाकात कर चर्चा की। कंपनी प्रमुखों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया का ध्यान भारतीय अर्थव्यवस्था पर केन्द्रित होता जा रहा है। देश की युवा आबादी और तेजी से तरक्की कर रहा मध्यम वर्ग भारतीय अर्थव्यवस्था में दुनिया की दिलचस्पी बढ़ा रहा है। खासतौर से यह दिलचस्पी विनिर्माण,व्यापार और वाणिज्य तथा दोनों देशों के लोगों के बीच सीधे संपर्क के क्षेत्र में देखी जा रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले तीन सालों में केन्द्र सरकार ने अपना सारा ध्यान लोगों की जीवन गुणवत्ता सुधारने पर केन्द्रित किया है। इसके लिए वैश्विक साझेदारी की दरकार है और इसलिए केन्द्र 'न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन' पर काम कर रही है। उन्होंने इस अवसर पर देश में हाल में हुए सुधारों की चर्चा करते हुए कहा कि अकेले केन्द्र की ओर से 7000 हजार सुधारों की पहल की गई है। यह भारत की वैश्विक मानक तय करने की चाहत को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार दक्षता, पारदर्शिता, विकास और सबके लाभ पर जोर दे रही है।

वस्तु एंव सेवा कर (जीएसटी) का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षों के अथक प्रयास के बाद यह अब वास्तविकता बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसे लागू करना एक जटिल कार्य है जो भविष्य के लिए अध्ययन का विषय हो सकता है। उन्होंने कहा कि जीएसटी को लागू करना यह दर्शाता है कि भारत बड़े फैसले लेने के साथ ही उन्हें तेजी से लागू करने का दम भी रखता है।

इस अवसर पर अमेरिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने नीतिगत पहलों और कारोबारी सहूलियतों के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की और इस क्रम में डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, कौशल विकास, विमुद्रीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में की गई पहलों की खासतौर से प्रशंसा की। कई कंपनी प्रमुखों ने सरकार के कौशल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में की गई पहलों में साझेदारी की इच्छा भी जताई।

उन्होंने इस मौके पर भारत में काम कर रही अमेरिकी कंपनियों द्वारा महिला सशक्तिकरण, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में किए जा रहे सामाजिक कार्यों का जिक्र भी किया।

बैठक में आधारभूत संरचना,रक्षा विनिमार्ण और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मसलों पर भी चर्चा की गई।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका और भारत समान मूल्यों को साझा करते हैं। यदि अमेरिका मजबूत होगा तो स्वाभाविक रूप से इसका फायदा भारत को मिलेगा। उन्होंने कहा कि एक शक्तिशाली अमेरिका पूरी दुनिया के लिए हितकारी होगा।

वाशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय से मिले प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 जून को वाशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय के लोगों से मिले। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि भारत से जब भी कोई कोई अच्छी खबर आती है अमेरिका में बसे भारतीय प्रवासी खुशी मनाते हैं और चाहते हैं कि भारत नयी ऊंचाइयों को छुए। उन्होंने प्रवासी भारतीयों की अमेरिकी अर्थव्यवस्था में योगदान की भूमिका की सराहना भी की।

उन्होने कहा कि भारत के लोगों को अब अवसर और बेहतर माहौल मिल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्दी ही ये लोग देश में भी बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि पिछले तीन सालो में केन्द्र सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका की विशेष रुप से चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के लाभों का विस्तार से जिक्र करते हुए कहा कि इससे

जहां तक अंतरराष्ट्रीय मुद्दों का सवाल है, हमारे दोनों देशों के विचार काफी हद तक एक जैसे हैं और नीदरलैंड की मदद से ही भारत ने पिछले साल एमटीसीआर की सदस्यता सफलतापूर्वक हासिल की और इसके लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं।

जरुरतमंदों तक सब्सिडी का लाभ पहुंचाने और इसमें किसी तरह की गड़बडी को रोकने में काफी मदद मिली है।

नीदरलैंड विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का पांचवां सबसे बड़ा स्रोत: मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 27 जून को नीदरलैंड पंहुचे। श्री मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और हमारे दोनों देश हमेशा से उन्हें कहीं अधिक गहराई देना और करीबी बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष हम भारत और नीदरलैंड

के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इसलिए यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि हम अपने द्विपक्षीय संबंधों पर कहीं अधिक ध्यान केंद्रित करें। आज की दुनिया एक-दूसरे पर निर्भर और एक-दूसरे से जुड़ी हुई दुनिया है। इसलिए यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि हमारे विचार-विमर्श में हम न केवल द्विपक्षीय मुद्दों पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा करें।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां तक अंतरराष्ट्रीय मुद्दों का सवाल है, हमारे दोनों देशों के विचार काफी हद तक एक जैसे हैं और नीदरलैंड की मदद से ही भारत ने पिछले साल एमटीसीआर की सदस्यता सफलतापूर्वक हासिल की और इसके लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां तक द्विपक्षीय निवेश का संबंध है, अब तक नीदरलैंड विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का पांचवां सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। वास्तव में पिछले तीन वर्षों के दौरान यह विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत था।

उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस तथ्य को दोहराने की कोई आवश्यकता है कि भारत के आर्थिक विकास में, विकास के लिए हमारी प्राथमिकताओं में, नीदरलैंड एक स्वाभाविक भागीदार है। आज हमें डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करने का भी अवसर मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि भारत के संबंध में उनका सकारात्मक दृष्टिकोण बरकरार रहेगा और मैं उनके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मुझे नीदरलैंड में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों से मिलने का भी अवसर मिलेगा। यहां रहने वाले भारतीय समुदाय दो देशों के बीच एक जीवंत लिंक और पुल के रूप में मौजूद हैं। लोगों से लोगों के संपर्क को और अधिक मजबूत करने का भी हमारा प्रयास है। ■

जीएसटी: गरीबों के उत्थान में सहायता प्रदान करने का महान साधन

प्रकाश चावला

संसद के भव्य केंद्रीय कक्ष में वस्तु एवं सेवा कर के शुभारम्भ के लिए राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उद्घाटित लघु और संक्षिप्त वीडियो में देश के अब तक के सबसे महत्वपूर्ण कर सुधार के स्पष्ट उद्देश्य को दर्शाया गया। जीएसटी किस तरह देश के सकल घरेलू उत्पाद को प्रोत्साहन देगा और व्यापार एवं उद्योग के लिए जीवन आसान बनाएगा, इस बारे में अर्थशास्त्रियों और अन्य टीकाकारों द्वारा हमें जो बताया जा रहा था, उसके विपरीत शुभारम्भ के अवसर पर प्रदर्शित फिल्म में आधुनिक कराधान के व्यापक पहलू को दिखाया गया, जिसके केंद्र में देश की जनता विशेषकर आर्थिक रूप से वंचित लोग हैं।

30 जून की मध्य रात्रि को, जीएसटी का शुभारम्भ करने से पहले अपने प्रेरक भाषण में, प्रधानमंत्री ने जीएसटी का उल्लेख गरीबों, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और अन्य पूर्वी राज्यों तथा पूर्वोत्तर के गरीबों के जीवन में बदलाव लाने के साधन के तौर पर किया। प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद, ये राज्य उन संसाधनों का उपयोग अपने विकास के लिए कर पाने में विफल रहे हैं।

इस पर गौर करते हुए प्रारंभ में यह पूछा जा सकता है कि जीएसटी देश के गरीबों के लिए किस तरह बेहद लाभकारी होगा या क्या यह पुराने ''ट्रिकल डाउन'' सिद्धांत की तरह व्यापार और उद्योग के जरिए भूमिका निभाने वाला होगा। कुछ हद तक ऐसा हो सकता है, लेकिन जीएसटी का स्वरूप उस बात को साकार करना सुनिश्चित करेगा, जो प्रधानमंत्री ने देश के बेहद विशिष्ट दर्शकों के समक्ष कही थी। देश की परिपक्व राजव्यवस्था और सहयोगपूर्ण संघवाद ने आखिरकार एक ऐसी प्रणाली प्रदान की है, जो आवश्यक तौर पर विनिर्माता केंद्रित न होकर लोक-केंद्रित है।

जिन राज्यों में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होगी, उन्हें कराधान में होने वाले लचीलापन के संदर्भ में अपार लाभ प्राप्त होगा, जिसे बाद में जनता और राज्यों के समग्र आर्थिक विकास के लिए कल्याणकारी योजनाओं में लगाया जाएगा।

उत्पाद शुल्क या अन्य शुल्कों के विपरीत जीएसटी, जिसमें सात केंद्रीय और आठ राज्य कर सम्मिलित हैं'- स्रोत या विनिर्माता

आधारित नहीं, बल्कि गंतव्य या उपभोक्ता केंद्रित है। स्पष्ट और सरल भाषा में कहें, तो जिन राज्यों में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होगी, उन्हें कराधान में होने वाले लचीलापन के संदर्भ में अपार लाभ प्राप्त होगा, जिसे बाद में जनता और राज्यों के समग्र आर्थिक विकास के लिए कल्याणकारी योजनाओं में लगाया जाएगा। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्य, जहां ज्यादा विनिर्माण आधार नहीं है और जिन्हें राजस्व की हानि हो रही है, उन्हें लाभ प्राप्त होगा, जबकि विकसित और विनिर्माण केंद्रों को जीएसटी के प्रारंभ के कम से कम पांच वर्षों के लिए क्षतिपूरित किया जाएगा। राज्य में जितने ज्यादा उपभोक्ता, उतना अधिक कर संग्रह, हालांकि उपभोक्ताओं को आर्थिक रूप से अधिकार सम्पन्न बनाने की जरूरत होगी!

विनिर्माण में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या कर्नाटक जैसे राज्यों के साथ कदमताल नहीं मिला सके इन राज्यों में व्यापार से वृद्धि को प्रोत्साहन प्राप्त होगा, बदले में बड़े पैमाने पर संसाधनों का सृजन होगा, ताकि उन्हें फिर से विकास के प्रयासों में लगाया जा सके। ऐसी जीवंतता आगे चलकर घरेलू और वैश्विक दोनों के निवेशकों की विनिर्माण और उससे संबंधित सेवा क्षेत्रों में दिलचस्पी का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन की संभावनाएं बनेंगी।

प्रधानमंत्री ने इस संदर्भ में कहा, ''जीएसटी ऐसी व्यवस्था है, जो देश के व्यापार में मौजूद अंसंतुलनों को समाप्त करेगी। यह देश के निर्यात को भी प्रोत्साहन देगी। यह व्यवस्था के पहले से विकसित राज्यों को ही बल नहीं प्रदान करेगी, बल्कि पिछड़े राज्यों को भी विकास का अवसर प्रदान करेगी। हमारे राज्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध हैं- बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर और ओडिशा की ओर देखिए। उन सभी में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं। जब उन्हें एकल कर व्यवस्था मिलेगी, तो मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं कि उनके यहां जो भी कमी है, उसे दूर कर दिया जाएगा और देश की यह कला आगे बढ़ेगी। भारत के समस्त राज्यों को विकास का समान अवसर प्राप्त होगा।''

'गंगानगर से लेकर ईटानगर तक' एक देश-एक कर के अलावा, श्री मोदी के शब्दों में कहें, तो इससे आर्थिक लेन-देन के ईमानदार तरीके को प्रोत्साहन देते हुए निश्चित तौर पर उद्योग, व्यापार और आम आदमी के लिए अलग-अलग तरह से जीवन आसान होगा। इसीलिए जीएसटी को ''गुड एंड सिम्पल टैक्स'' करार दिया गया है, जो शासन की नई संस्कृति लेकर आएगा।

प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ने ही जीएसटी को अमली जामा पहनाने का पूरा श्रेय विभिन्न राजनीतिक दलों और केंद्र तथा राज्यों की सरकारों को दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, ''यह किसी एक सरकार या दल की सिद्धी नहीं है. ये हम सबके साझे प्रयासों का परिणाम है।'' पिछली सरकार में वित्त मंत्री के रूप में उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर जीएसटी की यात्रा में अहम भूमिका निभाने वाले राष्ट्रपति ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा : "कर व्यवस्था का नया युग केन्द्र और राज्यों के बीच बनी व्यापक सहमति का परिणाम है। इस सहमति को बनने में केवल समय ही नहीं लगा, बल्कि इसके लिए अथक प्रयास भी करने पड़े। ये प्रयास राजनीतिक दलों की ओर से किए गए जिन्होंने संकीर्ण पक्षपातपूर्ण सोच को दरकिनार कर राष्ट्र हित को तरजीह दी। यह भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता और विवेक का प्रमाण है।"

नई कर व्यवस्था के प्रमुख फायदों में से एक 'कर पर कर' के कारण होने वाले व्यापक प्रभावों से मुक्त होना है। सुदृढ़ आईटी अवसंरचना के माध्यम से, इनपुट क्रेडिट की व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि वह कर-देयताओं के खिलाफ पारित और समायोजित की जाएं। इससे सिर्फ उपभोक्ताओं की मदद होगी। जाने-माने कर विशेषज्ञ श्री बृज भूषण का कहना है, ''वस्तुओं और सेवाओं के दामों

पिछली व्यवस्था में, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट और अन्य अप्रत्यक्ष करों के लिए क्रेडिट अंतिम वेंडर तक नहीं पहुंचता था, लेकिन जीएसटी में ऐसा क्रेडिट मूल्य श्रृंखला की अंतिम अवस्था में आपूर्तिकर्ता तक जाता है, जो बाद में उपभोक्ताओं को हस्तांतरित होता है।

में गिरावट आएगी। पिछली व्यवस्था में, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट और अन्य अप्रत्यक्ष करों के लिए क्रेडिट अंतिम वेंडर तक नहीं पहुंचता था, लेकिन जीएसटी में, ऐसा क्रेडिट मूल्य श्रृंखला की अंतिम अवस्था में आपूर्तिकर्ता तक जाता है, जो बाद में उपभोक्ताओं को हस्तांतरित होता है।

वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली भी उद्योग जगत को समझाते आ रहे हैं कि वह जीएसटी लागू होने के बाद प्राप्त हो रहे किसी भी प्रकार के लाभ को आगे बढ़ाए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि फायदों को आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए सरकार को लाभ-विरोधी प्राधिकरण के माध्यम से संभवतः अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा।

यहां तक कि राष्ट्रपति श्री मुखर्जी ने कहा कि प्रारंभिक अवस्था में कुछ रुकावटें हो सकती हैं, ये रचनात्मक रुकावट होगी। एक बार जब हम इन शुरूआती कठिनाइयों और समायोजन की आरंभिक अवधि को पार कर लेंगे, जीएसटी लोक-केंद्रित, जीवन में बदलाव लाने में सक्षम साबित होगा। ■

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

जीएसटी की शुरुआत राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण घटना: प्रणब मुखर्जी

'वस्तु और सेवा कर' के शुभारंभ से ठीक पहले राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 30 जून की अर्ध रात्रि के समय संसद के केंद्रीय कक्ष से राष्ट्र को संबोधित किया। यहां प्रस्तुत है उनके संबोधन का पूरा पाठ:

हम अब से कुछ मिनटों में देश में एक एकीकृत कर प्रणाली लांच होते हुए देखेंगे। यह ऐतिहासिक क्षण दिसंबर 2002 में प्रारंभ हुई चौदह वर्ष पुरानी यात्रा का परिणाम है जब अप्रत्यक्ष करों के बारे में गठित केलकर कार्य बल ने मूल्यवर्धित कर सिद्धांत पर आधारित विस्तृत वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लागू करने का सुझाव दिया था। जीएसटी का प्रस्ताव सबसे पहले वित्त वर्ष 2006-07 के बजट भाषण में आया था। प्रस्ताव में न केवल केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष कर में सुधार, बल्कि राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले करों में सुधार भी शामिल था। इसकी डिजाइन और इसे लागू करने के लिए कार्य योजना तैयार करने की जिम्मेदारी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति को दी गई जिसे पहले मूल्यवर्धित कर (वैट) लागू करने का दायित्व दिया गया था। अधिकार प्राप्त समिति ने नवंबर, 2009 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर पहला विर्मश पत्र जारी किया।

जीएसटी की शुरुआत राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। यह मेरे लिए भी संतोषजनक लम्हा है, क्योंकि बतौर वित्तमंत्री मैंने ही 22 मार्च 2011 को संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था। मैं इसकी रूपरेखा और कार्यान्वयन में बहुत गहराई से जुड़ा रहा और मुझे राज्य वित्तमंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के साथ औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही तरह की करीब 16 बार मुलाकात करने का अवसर भी मिला। मैंने गुजरात, बिहार, आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से भी कई बार मुलाकात की। उन मुलाकातों और उस दौरान उठाए गए मामलों की यादें आज भी मेरे ज़ेहन में हैं। इस कार्य की महत्ता को देखते हुए, जिसका दायरा संवैधानिक, कानूनी, आर्थिक और प्रशासनिक क्षेत्रों तक फैला हुआ था। इसमें विवादित मसले होना कोई हैरत की बात नहीं थी। तो भी, मुझे उन बैठकों में वे दोनों ही तरह के भाव मिले। राज्यों के मुख्यमंत्रियों, वित्तमंत्रियों और अधिकारियों के साथ अनेक बार विचार-विमर्श के दौरान मैंने पाया कि उनमें से अधिकांश का दृष्टिकोण रचनात्मक था और उनमें जीएसटी लाने के प्रति प्रतिबद्धता अंतर्निहित थी। इसलिए मैं इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि अब कुछ समय की ही बात है और जीएसटी आखिरकार लागू होकर रहेगा। मेरा विश्वास उस

समय सही साबित हुआ, जब 8 सितंबर 2016 को, संसद के दोनों सदनों तथा पचास प्रतिशत से अधिक राज्य विधानसभाओं द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। मुझे संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम को मंजूरी देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

संविधान में संशोधन के बाद, संविधान के अनुच्छेद 279 क के प्रावधानों के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन किया गया। जीएसटी के संबंध में संघ और राज्यों को सभी तरह की सिफारिशें जैसे आदर्श कानून, दरों, छूट के लिए उत्तरदायी है। परिषद हमारे संविधान में अनूठी हैं। यह केन्द्र और राज्यों का संयुक्त मंच है जहां केन्द्र और राज्य दोनों ही एक दूसरे के समर्थन के बिना कोई निर्णय नहीं ले सकते, वैसे तो संविधान में परिषद के निर्णय लेने की प्रकिया में

विस्तृत मतदान की व्यवस्था है, लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि परिषद की अब तक की 19 बैठकों में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। इस बात को लेकर आशंका थी कि राज्यों के बीच व्यापक विविधताओं को देखते हुए हजारों वस्तुओं की दरें निर्धारित करने का कार्य क्या जीएसटी परिषद द्वारा पूरा किया जा सकेगा या नहीं। परिषद ने इस कार्य को समय पर पूरा करके सभी को सुखद आश्चर्य की अनुभूति कराई है।

कर व्यवस्था के एक नए युग, जिसका सूत्रपात हम चंद ही मिनटों में करने जा रहे हैं, वह केन्द्र और राज्यों के बीच बनी व्यापक सहमति का परिणाम है। इस सहमति को बनने में केवल समय ही नहीं लगा, बल्कि इसके लिए अथक प्रयास भी करने पड़े। ये प्रयास राजनीतिक दलों की ओर से किए गए जिन्होंने संकीर्ण पक्षपातपूर्ण सोच को दरकिनार कर राष्ट्र हित को तरजीह दी। यह भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता और विवेक का प्रमाण है।

यहां तक कि कराधान और वित्त संबंधी मामलों से काफी हद तक जुड़े रहे मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी हमारे द्वारा किया जा रहा यह बदलाव वास्तव में चुनौतीपूर्ण है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का एक लम्बा इतिहास रहा है। वित्त मंत्री के रूप में मेरे विभिन्न कार्यकालों के दौरान केन्द्रीय कोष में यह सबसे अधिक योगदान करने वालों में से एक रहा है। सेवा शुल्क एक नया क्षेत्र है, लेकिन राजस्व के संदर्भ में इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वस्तु और सेवा कर के दायरे से बाहर कुछ वस्तुओं को छोड़कर अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क और विभिन्न उपकरों और अधिभारों के साथ अब ये दोनों समाप्त हो जाएंगे। वस्तु और सेवा के दायरे में आने वाली वस्तुओं के लिए अंतरराज्यीय बिक्री पर लगने वाला केन्द्रीय बिक्री कर खत्म हो जाएगा। राज्य स्तर पर बदलाव की संभावना कम नहीं है। सम्मिलित किये जा रहे मुख्य करों में मूल्यवर्धित, कर या बिक्री कर, प्रवेश शुल्क, राज्य स्तरीय मनोरंजन कर और विभिन्न उप करों और अधिभारों के साथ विज्ञापनों पर कर और विलासिता कर शामिल हैं।

जीएसटी हमारे निर्यात को और अधिक स्पर्धी बनाएगा तथा आयात से स्पर्धा में घरेलू उद्योग को एक समान अवसर उपलब्ध कराएगा। अभी हमारे निर्यात में कुछ अंतर-निहित कर जुड़े हुए हैं। इसलिए निर्यात कम स्पर्धी है। घरेलू उद्योग पर कुल कर भार पारदर्शी नहीं है। जीएसटी के अंतर्गत कर भार पारदर्शी होगा और इससे निर्यात पर कर बोझ पूरी तरह खत्म करने और आयात पर घरेलू कर भार समाप्त करने में सहायता मिलेगी।

मुझे बताया गया है कि जीएसटी एक आधुनिक विश्व स्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के जरिए लागू किया जाएगा। मुझे याद है कि मैंने जुलाई, 2010 में श्री नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में जीएसटी व्यवस्था के लिए आवश्यक आईटी प्रणाली विकसित करने के लिए अधिकार प्राप्त दल बनाया था। बाद में अप्रैल, 2012 में सरकार द्वारा जीएसटी लागू करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हिकल-जीएसटीएन (जीएसटी नेटवर्क) को स्वीकृति दी गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि हम समय व्यर्थ न करें और विधायी रूपरेखा तैयार होने के साथ-साथ तकनीकी अवसंरचना तैयार रहे और जीएसटी को आगे बढ़ाया जा सके। मुझे बताया गया कि इस प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह है कि इनपुट पर दिए गए कर के लिए खरीदार को क्रेडिट तभी मिलेगा, जब विक्रेता द्वारा वास्तविक रूप से सरकार को कर भुगतान कर दिया गया हो। इससे तेजी से बकाया भुगतान करने वाले ईमानदार और व्यवस्था परिपालन करने वाले विक्रेताओं से व्यवहार करने में खरीदारों को प्रोत्साहन मिलेगा।

एक एकीकृत समान राष्ट्रीय बाजार बनाकर जीएसटी आर्थिक सक्षमता, कर परिपालन तथा घरेलू और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने का काम करेगा। जीएसटी कठिन बदलाव है। यह वैट लागू होने से मिलता-जुलता है, जब शुरुआत में उसका भी विरोध हुआ था। जब इतने बड़े पैमाने पर बदलाव लाया जाने वाला हो, चाहे वह कितना ही

जीएसटी हमारे निर्यात को और अधिक स्पर्धी बनाएगा तथा आयात से स्पर्धा में घरेलू उद्योग को एक समान अवसर उपलब्ध कराएगा। अभी हमारे निर्यात में कुछ अंतर-निहित कर जुड़े हुए हैं। इसलिए निर्यात कम स्पर्धी है। घरेलू उद्योग पर कुल कर भार पारदर्शी नहीं है। जीएसटी के अंतर्गत कर भार पारदर्शी होगा और इससे निर्यात पर कर बोझ पूरी तरह खत्म करने और आयात पर घरेलू कर भार समाप्त करने में सहायता मिलेगी।

सकारात्मक क्यों न हो, शुरुआती अवस्था में थोड़ी-बहुत कठिनाइयां और परेशानियां तो होती ही हैं। हमें इन सबको समझदारी के साथ और तेजी से सुलझाना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था की वृद्धि की रफ्तार पर नहीं पड़ेगा। ऐसे बड़े बदलावों की सफलता हमेशा उनके प्रभावी कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। आने वाले महीनों में, इसके वास्तविक कार्यान्वयन के अनुभवों के आधार पर जीएसटी परिषद तथा केंद्र और राज्य सरकारें अब तक प्रदर्शित की जा रही रचनात्मक भावना के साथ लगातार इसकी रूपरेखा की समीक्षा करती रहां और इसमें सुधार लाती रहें।

अब जबकि हम एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार की रचना का प्रारंभ करने जा रहे हैं, ऐसे में, मैं प्रत्येक भारतवासी से इस नई व्यवस्था के सफल कार्यान्वयन में सहयोग देने के आह्वान के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। ■

सहकारी संघवाद की अद्भुत मिसाल 'जीएसटी': नरेंद्र मोदी

संसद के केंद्रीय कक्ष से 30 जून की अर्ध-रात्रि के समय स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा कर सुधार 'वस्तु और सेवा कर' (जीएसटी) लागू हो गया। जीएसटी लागू होने से कुछ क्षण पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संसद के केंद्रीय कक्ष से जीएसटी की अनिवार्यता और उपयोगिता पर सारगर्भित विचार व्यक्त किये। यहां प्रस्तुत है उनके संबोधन के मुख्य अंश:

राष्ट्र के निर्माण में कुछ ऐसे पल आते हैं जिस पल पर हम किसी नए मोड़ पर जाते हैं, नए मुकाम की ओर पहुंचने का प्रयास करते हैं। आज इस मध्य रात्रि के समय हम सब मिल करके देश का आगे का मार्ग सुनिश्चित करने जा रहे हैं।

कुछ देर बाद, देश एक नई व्यवस्था की ओर चल पड़ेगा। सवा सौ करोड़ देशवासी इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी हैं। जीएसटी की ये प्रक्रिया, ये सिर्फ अर्थव्यवस्था के दायरे तक सीमित है, ऐसा मैं नहीं मानता। पिछले कई वर्षों से अलग-अलग महानुभावों के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में, अलग-अलग टीमों के द्वारा जो प्रक्रियाएं चली हैं, वो एक प्रकार से भारत के लोकतंत्र की भारत की, संघीय ढांचे की, सहकारी संघवाद के हमारे अवधारणा की एक बहुत बड़ी मिसाल के रूप में आज ये अवसर हमारा आया है। इस पवित्र अवसर पर आप सब अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आए हैं। मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं।

ये जो दिशा हम सबने निर्धारित की है, जो रास्ता हमने चुना है, जिस व्यवस्था को हमने विकसित किया है। यह किसी एक दल की सिद्धि नहीं है, यह किसी एक सरकार की सिद्धि नहीं है, ये हम सबकी सांझी विरासत है, हम सबके सांझे प्रयासों का परिणाम है।

संविधान का मंथन 2 साल, 11 महीने और 17 दिन तक चला था। हिन्दुस्तान के कोने-कोने से विद्वतजन उस बहस में हिस्सा लेते थे, वाद-विवाद होते थे, राजी-नाराजी होती थी, सब मिल करके बहस करते थे, रास्ते खोजते थे। कभी इस पार, कभी उस पार नहीं जा पाए, तो बीच का रास्ता खोज करके चलने का प्रयास करते थे। ठीक उसी तरह ये जीएसटी भी एक लम्बी विचार-प्रक्रिया का परिणाम है। सभी राज्यों समान रूप से, केन्द्र सरकार उसी की बराबरी में और सालों तक चर्चा की है। संसद में इसके पूर्व के भी सांसदों ने, उसके पूर्व के सांसदों ने लगातार इस पर बहस की है। एक प्रकार से best brains of the country उन्होंने लगातार इस काम को किया है और उसी का परिणाम है कि आज ये जीएसटी को हम साकार रूप में देख सकते हैं।

जब संविधान बना तो संविधान ने पूरे देश के नागरिकों को समान अवसर, समान अधिकार, उसके लिए सुनिश्चित व्यवस्था खड़ी कर दी थी और आज जीएसटी एक प्रकार से सभी राज्यों के मोतियों को एक धागे में पिरोने का और आर्थिक व्यवस्था के अंदर एक सुचारू व्यवस्था लाने का एक अहम प्रयास है। जीएसटी एक सहकारी संघवाद की एक मिसाल है, जो हमें हमेशा-हमेशा और अधिक साथ मिलकर चलने की ताकत देगी। जीएसटी, ये 'टीम इंडिया' का क्या परिणाम हो सकता है, इस 'टीम इंडिया' की कर्तव्य शक्ति का, सामर्थ्य का परिचायक है।

ये जीएसटी परिषद केंद्र और राज्य में मिल करके उन व्यवस्थाओं को विकसित किया है, जिसमें गरीबों के लिए जो पहले उपलब्ध सेवाएं थीं, उन सारी सेवाओं को बरकरार रखा है। दल कोई भी हो, सरकार कहीं की भी हो; गरीबों के प्रति संवेदनशीलता इस जीएसटी के साथ जुड़े हुए सब लोगों ने समान रूप से उसकी चिंता की है।

आज जीएसटी परिषद की 18वीं मीटिंग हुई और थोड़ी देर के बाद जीएसटी लागू होगा। ये भी संजोग है कि गीता के भी 18 अध्याय थे और जीएसटी परिषद की भी 18 मीटिंगें हुई और आज हम उस सफलता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। एक लंबी प्रक्रिया थी, परिश्रम थी, शंकाएं, आशंकाएं थीं, राज्यों के मन में गहरे सवाल थे, लेकिन अथाह पुरूषार्थ, परिश्रम, दिमाग की जितनी भी शक्ति उपयोग में लाई जा सकती है लाकर के इस कार्य को पार किया है।

हम कल्पना करें कि देश आज़ाद हुआ, 500 से ज्यादा रियासतें थीं। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों को मिलाकर के देश को एक न किया होता, देश का एकीकरण न किया होता तो भारत का राजनीतिक मानचित्र कैसा होता? कैसा बिखराव होता! आजादी होती लेकिन देश का वो मानचित्र कैसा होता? जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को मिला करके एक राष्ट्रीय एकीकरण का बहुत बड़ा काम किया था, आज जीएसटी के द्वारा आर्थिक एकीकरण का एक महत्वपूर्ण काम हो रहा है। 29 राज्य, 7 केन्द्र शासित प्रदेश, केन्द्र के 7 टैक्स, राज्यों के 8 टैक्स और हर चीजों के अलग-अलग टैक्स का हिसाब लगाएं, तो 500 प्रकार के टैक्स कहीं न कहीं अपनी भूमिका निभा कर रहे थे। आज उन सबसे मुक्ति पाकर के, अब गंगानगर से ले करके इटानगर तक, लेह से ले करके लक्षद्वीप तक एक राष्ट्र- एक कर यह सपना हमारा साकार होकर रहेगा।

और जब इतने सारे टैक्स, 500, अलग-अलग हिसाब लगाएं 500 टैक्स। अलबर्ट आइंसटीन प्रखर वैज्ञानिक उन्होंने एक बार बड़ी मज़ेदार बात कही थी। उन्होंने कहा था कि दुनिया में अगर कोई चीज समझना सबसे ज्यादा मुश्किल है तो वो है आयकर, यह अलबर्ट

जब संविधान बना तो संविधान ने पूरे देश के नागरिकों को समान अवसर, समान अधिकार, उसके लिए सुनिश्चित व्यवस्था खड़ी कर दी थी और आज जीएसटी एक प्रकार से सभी राज्यों के मोतियों को एक धागे में पिरोने का और आर्थिक व्यवस्था के अंदर एक सुचारू व्यवस्था लाने का एक अहम प्रयास है। जीएसटी एक सहकारी संघवाद की एक मिसाल है, जो हमें हमेशा-हमेशा और अधिक साथ मिलकर चलने की ताकत देगी। जीएसटी, ये 'टीम इंडिया' का क्या परिणाम हो सकता है, इस 'टीम इंडिया' की कर्तव्य शक्ति का, सामर्थ्य का परिचायक है।

आइंसटीन ने कहा था। मैं सोच रहा था अगर वो यहां होते तो पता नहीं ये सारे टैक्स देखकर के क्या कहते, क्या सोचते? और इसलिए, और हमने देखा है कि उत्पाद के अंदर के उत्पादन में तो ज्यादा कोई बहुत असमानता नहीं आती है, लेकिन जब प्रॉडक्ट बाहर जाता है तो राज्यों के अलग-अलग टैक्स के कारण असमानता दिखती है। एक ही चीज दिल्ली में एक दाम होगा, 25-30 किलोमीटर गुरूग्राम में दूसरा चार्ज लगेगा और उधर नोएडा में गए तो तीसरा होगा। क्यों, क्योंकि हरियाणा का टैक्स अलग, उत्तर प्रदेश का टैक्स अलग, दिल्ली का अलग। इन सारी विविधताओं के कारण सामान्य नागरिक के मन में सवाल उठता था कि मैं गुरूग्राम में जाता हूं तो यही चीज मुझे इतने में मिल जाती है, वही चीज नोएडा में जाऊं तो इतने में मिलती है और दिल्ली में जाता हूं तो इतने में मिलती है। एक प्रकार से हर किसी के

लिए कन्फ्यूजन की स्थिति रहती थी। अब पूंजी निवेश में भी विदेशों के लोगों के लिए यह सवाल रहता था कि भई किस, एक व्यवस्था हम समझते हैं और काम कहीं सोचते हैं, तो दूसरे राज्य में दूसरी व्यवस्था सामने आती है और एक कन्फ्यूजन का माहौल बना रहता था, आज उससे मुक्ति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं।

अरुण जी ने बड़ा विस्तार से वर्णन किया है कि जीएसटी के कारण Octroi की व्यवस्था हो, एंट्री टैक्स हो, सेल टैक्स हो, वैट हो, न जाने कितनी चीजें, सारा वर्णन उन्होंने विस्तार से किया सब खत्म हो जाएगा। हम जानते हैं कि हम एंट्री के टोल पर घंटों तक हमारे वाहन खड़े रहते हैं। देश का अरबों खरबों का नुकसान होता है। ईंधन के जलने के कारण पर्यावरण का भी उतना ही नुकसान होता है। इस सारी व्यवस्था एकसमान होने के कारण, एक प्रकार से उन सारी अव्यवस्थाओं में से एक मुक्ति का मार्ग हमें प्राप्त होगा।

कभी-कभार खराब होने वाला माल खासकरके समय पर पहुंचना बहुत आवश्यक होता था, लेकिन वो जब नहीं पहुंचता था तो उसके कारण उस पहुंचाने वाले का भी नुकसान होता था और जो Processing करता था उसका भी नुकसान होता था। इन सारी जो व्यवहार जीवन की अव्यवस्थाएं थीं, उन अव्यवस्थाओं से आज हम मुक्ति पा रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं।

जीएसटी के तौर पर देश एक आधुनिक कर प्रणाली की ओर आज कदम रख रहा है, बढ़ रहा है। एक ऐसी व्यवस्था है जो ज्यादा सरल है, ज्यादा पारदर्शी है; एक ऐसी व्यवस्था है जो जो काले धन को और भ्रष्टाचार को रोकने में एक अवसर प्रदान करती है। एक ऐसी व्यवस्था है जो ईमानदारी को अवसर देती है, जो ईमानदारी से व्यापार करने के लिए एक उमंग, उत्साह करने की व्यवस्था इससे मिलती है। एक ऐसी व्यवस्था है जो नए गवर्नेंस के कल्चर को भी ले करके आती है और जिसके द्वारा जीएसटी हम लेकर आए हैं।

कर आतंक और इंस्पेक्टर राज, ये बात कोई नई नहीं है। सब दूर ये शब्द हम सुनते आए हैं, परेशानी भुगतने वालो से हमने उस चिंता को अनुभव किया है और जीएसटी की इस व्यवस्था के कारण Technologically के लिए सारा ट्रेल होने के कारण, अब अफसरशाही, सब उसके लिए ग्रे एरिया बिलकुल समाप्त हो रहा है। उसके कारण जो सामान्य व्यापारियों को, सामान्य कारोबारियों को अफसरों के द्वारा जो परेशानियां होती रही है, उससे मुक्ति का मार्ग इस जीएसटी के द्वारा, कोई ईमानदार व्यापारी बेवजह परेशान हो वो दिन इसके साथ खत्म होने की पूरी संभावना इस जीएसटी के अंदर है। इस पूरी व्यवस्था में, छोटे व्यापारियों को 20 लाख तक का व्यापार करने वालों को पूरी तरह मुक्ति दे दी गई है और जो 75 लाख तक हैं, उनको भी कम से कम इस चीजों से जुड़ना पड़े इसकी व्यवस्था की है। ये बात ठीक है कि स्ट्रक्चर में लाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन वो मिनिमम व्यवस्थाएं, नाममात्र की व्यवस्थाएं की गई हैं और उसके कारण सामान्य मानवी जो है, उसके लिए इस नई व्यवस्था से कोई बोझ होने वाला नहीं है।

जीएसटी की व्यवस्था, ये बड़ी-बड़ी आर्थिक भाषा में जो बोला जाता है, वहां तक सीमित नहीं है। बड़े-बड़े शब्द इसके साथ जोड़े जाते हैं, लेकिन अगर सरल भाषा में कहें कि देश के गरीबों के हित के लिए ये व्यवस्था सबसे ज्यादा सार्थक होने वाली है। आजादी के 70 साल के बाद भी हम गरीबों तक जो पहुंचा नहीं पाए हैं, ऐसा नहीं कि प्रयत्न नहीं हुए हैं। सब सरकारों ने प्रयत्न किए हैं, लेकिन संसाधनों की मर्यादा रही है कि हम हमारे देश के गरीब की उन आवश्यकताओं की पूर्ति में कहीं न कहीं कम पड़े हैं।

अगर हम संसाधनों को सुव्यस्थित ढंग से और बोझ किसी एक पर न जाएं, बोझ sparred हो जाएं, Horizontal जितना हम sparred करें, उतना ही देश को Vertical ले जाने की सुविधा बढ़ती है। और इसलिए उस दिशा में जाने का काम, अब वो कच्चा बिल, पक्का बिल, ये सारे खेल खत्म हो जाएंगे, बड़ी सरलता हो जाएगी। और मुझे विश्वास है छोटे-मोटे व्यापारी भी, ये जो गरीब को लाभ मिलने वाला है, वो जरुर उसको ट्रांसफर करेंगे, ताकि गरीब का भला, हम लोगों का आगे बढ़ाने के लिए बहुत-बहुत काम आने वाला है।

जीएसटी के तौर पर देश एक आधुनिक कर प्रणाली की ओर आज कदम रख रहा है, बढ़ रहा है। एक ऐसी व्यवस्था है जो ज्यादा सरल है, ज्यादा पारदर्शी है; एक ऐसी व्यवस्था है जो जो काले धन को और भ्रष्टाचार को रोकने में एक अवसर प्रदान करती है। एक ऐसी व्यवस्था है जो ईमानदारी को अवसर देती है, जो ईमानदारी से व्यापार करने के लिए एक उमंग, उत्साह करने की व्यवस्था इससे मिलती है। एक ऐसी व्यवस्था है जो नए गवर्नेंस के कल्चर को भी ले करके आती है और जिसके द्वारा जीएसटी हम लेकर आए हैं।

कभी-कभी आशंकाएं होती हैं कि ये नहीं होगा, ढिकना नहीं होगा, फलाना नहीं होगा और हमारे देश में हम जानते हैं कि जब 11वीं और 12वीं के रिजल्ट ऑनलाइन देने की शुरूआत की और एक साथ सब गए जब, तो सारा हैंग-अप हो गया और दूसरे दिन खबर यही बन गई कि ऐसा हो गया। आज भी काफी ऐसी ही चर्चा होती है।

ये बात ठीक है कि हर किसी को टेक्नोलॉजी नहीं आती है, लेकिन हर परिवार में दसवीं, बारहवीं का अगर विद्यार्थी है, तो उसको ये सारी चीजें आती हैं। कोई मुश्किल काम नहीं, इतना सरल है, घर में 10वीं,

12वीं का विद्यार्थी भी रहता है, वो चीजें छोटे से व्यापारी को भी और वो मदद कर सकता है, एक रास्ता निकल सकता है।

जो लोग आशंकाएं करते हैं, मैं कहता हूं कृपा करके ऐसा मत कीजिए। अरे आपका पुराना डॉक्टर हो, आप उसी से अपनी आंखें लगातार चेक करवाते हो। वो ही हर बार आपके नंबर निकालता हो, आपका चश्मा बनाने वाला भी निश्चित हो, आप वहां अपने नंबर बनवाते हो, और फिर भी जब नया नंबर वाला चश्मा आता है तो एकाध-दो दिन तो आंख ऊपर-नीचे करके एडजस्ट करना पड़ता है; ये बस इतना ही है। इसलिए थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे इस व्यवस्था के साथ हम आसानी से जुड़ जाएंगे। और इसलिए थोड़ा सा अगर हम प्रयास करेंगे तो इस व्यवस्था से हम आसानी से जुड़ जाएंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अफवाहों के बाजार को बंद करें और अब, जब देश चल पड़ा है तो सफल कैसे हो, देश के गरीब-जनों की भलाई के लिए कैसे काम हो, उस पर हम ले करके चलें और तब जा करके कम होगा।

जीएसटी के इस निर्णय का, वैश्विक आर्थिक जगत में एक बहुत सकारात्मक प्रभाव हुआ है। भारत में जो पूंजी निवेश करना चाहते हैं उनके लिए भी एक प्रकार की व्यवस्था बहुत आसानी से वो समझ पाते हैं और उसको चला पाते हैं। मैं समझता हूं भारत में और आज दुनिया का एक प्रिय गंतव्य के रूप में, निवेश के लिए प्रिय गंतव्य के रूप में भारत को हर प्रकार से स्वीकृति मिली है और इसके लिए मैं समझता हूं कि एक अच्छी सुविधा विश्व–व्यापार से जुड़े हुए लोगों को भी भारत के साथ व्यापार करने के लिए मिलेगी।

जीएसटी एक ऐसा उत्प्रेरक है जो देश के व्यापार को, उसमें जो असंतुलन है, उस असंतुलन को खत्म करेगा। जीएसटी एक ऐसा उत्प्रेरक है जिससे निर्यात संबर्धन को भी बहुत बल मिलेगा। जीएसटी एक वो व्यवस्था है, जिसके कारण आज हिन्दुस्तान में जो राज्य ठीक से विकसित हुए हैं, उनको विकास के अवसर तुरंत मिलते हैं, लेकिन जो राज्य पीछे रह गए हैं, उनको वो अवसर तलाशने में बहुत दम घोटना पड़ता है। उन राज्यों का कोई दोष नहीं है। प्राकृतिक संपदा से समृद्ध हैं, हमारा बिहार देखें, हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश देखें, हमारा पश्चिम बंगाल देखें, हमारे नॉर्थ-ईस्ट के देखें, हमारा उड़ीसा देखें, संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों से भरे पड़े हैं। लेकिन अगर उनको ये, ये व्यवस्था, जब एक कानून की व्यवस्था मिल जाएगी, मैं साफ देख रहा हूं कि हिन्दुस्तान का पूर्वी हिस्सा के विकास में मैं जो कुछ भी कमी रह गई है, उसको पूरा करने का सबसे बड़ा अवसर, सबसे बड़ा अवसर इससे मिलने वाला है। हिन्दुस्तान के सभी राज्यों को विकास के समान अवसर प्राप्त होना, ये अपने-आप में विकास की राह पर आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा अवसर है।

जीएसटी, एक प्रकार से जैसे हमारी रेलवे है। रेलवे- केंद्र और राज्य मिल करके चलाते हैं, फिर भी भारतीय रेल के रूप में हम देखते हैं। राज्य के अंदर स्थानीय रूप से मदद मिलती है, एक समान रूप से हम देखते हैं। हमारे केंद्रीय सेवा के अधिकारी केंद्र और राज्यों में वितरित हैं, फिर भी दोनों तरफ से मिल करके चला सकते हैं। एक जीएसटी ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें पहली बार केंद्र और राज्य के लोग मिल करके निश्चित दिशा में काम करने वाले हैं। ये अपने-आप में 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के लिए एक उत्तम से उत्तम व्यवस्था आज हो रही है, और जिसका प्रभाव आने वाले दिनों में, आने वाली पीढ़ियां हमें गर्व के साथ स्वीकार करेंगी।

2022, भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं। 'नए भारत' का सपना ले करके हम चल पड़े हैं। सवा सौ करोड़ देशवासी 'नए भारत' बनाने के सपनों को ले करके चल रहे हैं और इसलिए जीएसटी एक अहम भूमिका अदा करेगी और हम लोगों ने जिस प्रकार से प्रयास किया है। जीएसटी 'नए भारत' की एक टैक्स व्यवस्था है।

जीएसटी के इस निर्णय का, वैश्विक आर्थिक जगत में एक बहुत सकारात्मक प्रभाव हुआ है। भारत में जो पूंजी निवेश करना चाहते हैं उनके लिए भी एक प्रकार की व्यवस्था बहुत आसानी से वो समझ पाते हैं और उसको चला पाते हैं। मैं समझता हूं भारत में और आज दुनिया का एक प्रिय गंतव्य के रूप में, निवेश के लिए प्रिय गंतव्य के रूप में भारत को हर प्रकार से स्वीकृति मिली है और इसके लिए मैं समझता हूं कि एक अच्छी सुविधा विश्व–व्यापार से जुड़े हुए लोगों को भी भारत के साथ व्यापार करने के लिए मिलेगी।

जीएसटी 'डिजिटल भारत' की टैक्स व्यवस्था है। जीएसटी सिर्फ 'Ease of doing Business' नहीं है, जीएसटी 'Way of Doing Business' की भी एक दिशा दे रहा है। जीएसटी सिर्फ एक टैक्स सुधार नहीं है, लेकिन वो आर्थिक सुधार का भी एक अहम कदम है। जीएसटी आर्थिक सुधार से भी आगे एक सामाजिक सुधार का भी एक नया तबका, जो एक ईमानदारी के उत्सव की ओर ले जाने वाला ये बन रहा है। कानून की भाषा में जीएसटी-वस्तु और सेवा कर के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन जीएसटी से जो लाभ मिलने वाले हैं और इसलिए मैं कहूंगा कि कानून भले ही कहता हो कि वस्तु और सेवा कर, लेकिन हकीकत में ये Good and Simple Tax है और Good इसलिए कि टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स जो लगते थे, उससे मुक्ति मिल गई। सिंपल इसलिए है कि पूरे देश में एक ही फॉर्म होगा, एक ही व्यवस्था होगी और उसी व्यवस्था से चलने वाला है और इसलिए उसे हमें आगे बढ़ाना है। ■

'वस्तु और सेवा कर' एक महत्वाकांक्षी कर सुधार: अरुण जेटली

यहां प्रस्तुत है संसद के केंद्रीय कक्ष से वस्तु और सेवा कर के शुभारम्भ पर वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली के संबोधन के मुख्य अंश:

हम आज यहां, अपने देश की यात्रा के महत्वपूर्ण क्षण के लिए एकत्रित हुए हैं। हम इतिहास बनाने की प्रक्रिया में हैं। मध्य रात्रि को वस्तु और सेवा कर लांच होने के साथ हम अपने इतिहास का सबसे बड़ा और सर्वाधिक महत्वकांक्षी कर तथा आर्थिक सुधार कार्यक्रम लांच करेंगे। जीएसटी भले ही गंतव्य कर हो, लेकिन भारत के लिए एक नई यात्रा की शुरूआत है। एक ऐसी यात्रा है, जहां भारत अपने आर्थिक क्षितिज और गौरवशाली राजनीतिक विज़न को विस्तार देने की असीम संभावनाओं के लिए जगेगा। पुराना भारत आर्थिक दृष्टि से खण्डित था, नया भारत एक देश के लिए एक कर, एक बाजार बनाएगा। एक ऐसा भारत होगा, जहां केन्द्र और राज्य साझी समृद्धि के समान लक्ष्य के लिए एक साथ सहयोगी और सदभावपूर्ण भाव से काम करेंगे। ऐसा भारत होगा, जो नई नियति लिखेगा।

जीएसटी पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जीएसटी काउंसिल के सहमति आधारित कार्य में संविधान संशोधन के लिए सर्वसम्मत समर्थन यह दिखाता है कि भारत संकुचित राजनीति से ऊपर उठ सकता है और व्यापक राष्ट्रीय हित के लिए एक स्वर में बोल सकता है। संविधान संशोधन तथा जीएसटी परिषद में गुणवत्ता संपन्न और परिपक्व बहस इस बात का परिचायक है कि भारत सामूहिक रूप से सोच सकता है और व्यापक उद्देश्य के लिए परिपक्कता के साथ कार्य कर सकता है।

संविधान कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। संघ तभी शक्तिशाली होगा, जब राज्य और केन्द्र दोनों मजबूत हों। सहयोगी संघवाद की यही वास्तविक अर्थ है। जीएसटी बनाते हुए न तो केन्द्र ने और न ही राज्यों ने अपनी संप्रभुता छोड़ी। उन्होंने अपनी संप्रभुता को प्रत्यक्ष कराधान पर संयुक्त निर्णय करने के लिए आगे बढ़ाया है।

केन्द्र, विधानसभाओं सहित 29 राज्यों और दो संघ शासित प्रदेशों तथा व्यापक वैविध्यपूर्ण हितों वाले बहुदलीय लोकतंत्र की विशाल और जटिल प्रणाली में हमने संविधान संशोधन लागू किया और भारतीय राजनीति के उत्कर्ष को प्रदर्शित करते हुए विशाल कर सुधार को अंजाम दिया। हमने यह कार्य ऐसे समय में किया है, जबकि समूचा विश्व धीमी वृद्धि, पृथकतावाद और संरचनात्मक सुधारों के अभावों से जूझ रहा है। जीएसटी के माध्यम से भारत ने यह दिखा दिया है कि समावेशन, खुलेपन और साहस के साथ इन ताकतों पर काबू पाया जा

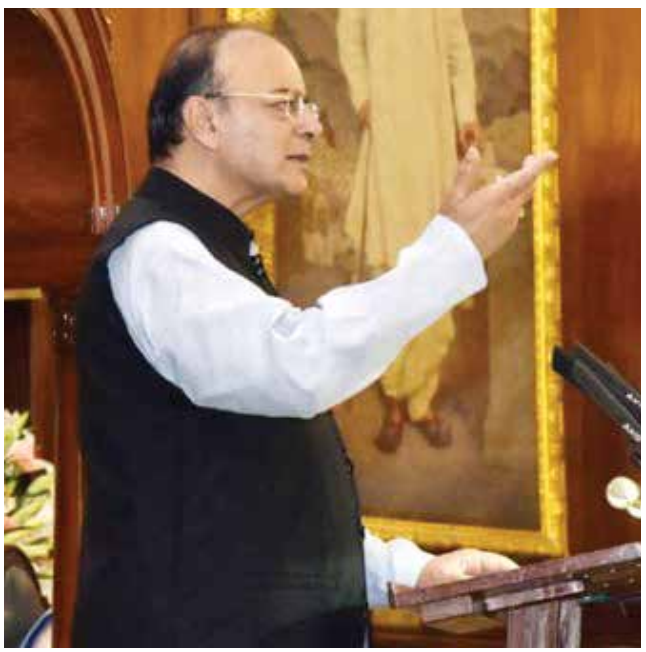

सकता है। इस कार्य में योगदान देने वाले सभी सांसदों, राज्य सरकारों, समस्त राजनीतिक दलों, राज्यों के वित्त मंत्रियों तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों के हमारे अधिकारियों की समर्पित टीम की व्यापक सराहना की जानी चाहिए और इनका आभार प्रकट करना चाहिए।

राष्ट्रपति जी ये जो यात्रा थी आप इसके सबसे प्रमुख गवाह हैं कि लगभग 15 वर्ष से पहले आरंभ हुई थी। एनडीए-1 सरकार ने एक समिति की रचना की थी जिसके अध्यक्ष श्री विजय केलकर इस सभागार में मौजूद है। उन्होंने सन 2003 में एक एतिहासिक रिपोर्ट दी थी। कि इस देश के अंदर एक वैल्यू बेस्ड Taxation GST के नाम से आरंभ किया गया। 2006 के बजट में यूपीए सरकार ने घोषणा की थी कि 2010 तक इसको लागू करने का प्रयास होगा और 2011 के बजट में जब महामहिम राष्ट्रपति जी ने उस वक्त वित्त मंत्री की हैसियत में बजट पेश किया था तो उसके तुरंत बाद आपने संविधान संशोधन भी देश के सामने रखा था। जिसके माध्यम से राज्य और

केंद्र अपने अधिकारों को एकत्रित करके वस्तु और सेवा कर की रचना करें। आपकी उस संविधान संशोधन के बाद संसद की Standing Committee उसने बहुत योगदान लायक सुझाव दिए थे। यशवंत सिन्हा जी आज मौजूद है इस सभागार में, वो उसके अध्यक्ष थे और उसका सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक थी कि जीएसटी परिषद की रचना की जाए जिसमें एक तिहाई वोट केंद्र का होगा, दो तिहाई वोट राज्यों के होंगे, लेकिन निर्णय करने के लिए तीन चौथाई बहुमत की आवश्यकता है। Standing Committee के उस निर्णय का ये असर था कि केंद्र और राज्यों को संवैधानिक दृष्टि से इकट्ठा काम करने के लिए मजबूर किया गया और जीएसटी परिषद में जो एक प्रकार से सहमति बनी, उसमें इसका एक बहुत बड़ा योगदान Standing Committee के उस सुझाव का था।

एक समानांतर रचना राज्यों के वित्त मंत्रियों की थी, एक Empowered Committee थी और समय-समय पर हर सरकार ने एक परंपरा बनाई कि किसी विरोधी पक्ष के दल की जिस राज्य की सरकार हो, उसका कोई वित्त मंत्री उस Empowered Committee का अध्यक्ष रहे। पहले अध्यक्ष श्री डॉ. असीम दास गुप्ता हमारे बीच में हैं और बहुत वर्षो तक देश में उन्होंने सहमति बनाने का एक बहुत बड़ा काम किया। मुझे स्वयं उनका आभार इसलिए भी व्यक्त करना है कि मुझे पहली शिक्षा जीएसटी पे उनसे ही मिली थी, एक बैठक में।

प्रोफेसर दास गुप्ता के बाद जम्मू -कश्मीर के श्री अब्दुल रहीम राथर, श्री सुशील मोदी उसके बाद केरल के श्री के. एम. मणि और बंगाल के डॉ. अमित मित्रा, ये एक राज्यों के बीच में आम राय बनाते रहे। और इस पूरे इतिहास के बाद इस देश ने कि राजनीति ने ऐसी एक परिपक्वता का एक उदाहरण पेश किया जिसका सबसे बड़ा सबूत ये था कि संविधान संशोधन संसद के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पारित हुआ जिससे जीएसटी परिषद की रचना हुई। उस रचना के बाद परिषद की पहली जिम्मेवारी थी कि केंद्र के लिए और राज्यों के लिए कानून बनाए। वो सभी कानून पांच केंद्र के लिए एक सभी राज्यों के लिए सर्वसम्मति से बनें। संसद ने उसे सर्वसम्मति से पास किया, राज्यों ने एकमत से पास किया और आज वो एक वास्तविक्ता के रूप में हमारे सामने आया है। जीएसटी परिषद 18 बार मिल चुकी है। कुछ बैठकें सुबह से शाम तक और दो-दो तीन-तीन दिन चलती हैं और एक भी निर्णय पर वोट करवाने की आज तक आवश्यकता नहीं पड़ी। हर एक निर्णय सर्वसम्मति से हुआ जिसमें अलग-अलग राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि थे, अलग-अलग राज्य सरकारों के प्रतिनिधि थे, और एक मत से हर निर्णय उसमें हुआ अभी तक 24 Regulations बन चुके हैं। राज्य और केन्द्र के अधिकार क्षेत्र के बारे में बंटवारा क्या रहेगा उसमें निर्णय हो चुका है। 1211 commodities हैं, जिस पर Taxation तय करना था। बिना मतभेद के, बिना किसी Dissent के एक एक Commodity का टैक्स सर्वमत से तय हुआ और उसके पीछे भी दो सिद्धांत थे कि एक आम और गरीब आदमी पर ज्यादा बोझ न पड़े। Revenue Neutral रहे कि जितना राजस्व राज्य और केन्द्र इकट्ठा करते हैं कम से कम वो बरकरार रहे और जो मौजूदा Taxation ढांचा है उससे बहुत अधिक किसी के ऊपर बोझ न पड़े।

आज की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में राज्यों और केन्द्र को मिलाकर 17 Transaction टैक्स हैं- 23 सेस हैं, उन सबको समाप्त कर दिया गया है और उनके स्थान पर केवल एक टैक्स रहेगा। उस हर टैक्स के लिए अलग रिटर्न जाता था, आज एक रिटर्न जाएगा। हर एक assesse को अलग-अलग taxation अधिकारियों के साथ interface करना पड़ता था। आज केवल उसको अपने साफ्टवेयर के साथ एक रिटर्न के माध्यम से interface करना पड़ेगा और केवल साफ्टवेयर के ऊपर registration ले लेना और उस registration के बाद हर महीने की दस तारीख तक केवल एक फार्म भरना computer पर कि मेरी पिछले महीने की transaction क्या है, उसमें डाल देना और उसके माध्यम से टैक्स के ऊपर टैक्स न लगना, ये इसकी एक विशेषता है।

आज की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में राज्यों और केन्द्र को मिलाकर 17 Transaction टैक्स हैं- 23 सेस हैं, उन सबको समाप्त कर दिया गया है और उनके स्थान पर केवल एक टैक्स रहेगा। उस हर टैक्स के लिए अलग रिटर्न जाता था, आज एक रिटर्न जाएगा। हर एक assesse को अलग-अलग taxation अधिकारियों के साथ interface करना पड़ता था। आज केवल उसको अपने साफ्टवेयर के साथ एक रिटर्न के माध्यम से interface करना पड़ेगा।

पूरे देश के अंदर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग रेट और चुंगी-नाकों के ऊपर ट्रकों की भीड़ वो समाप्त होगी और एक प्रकार से single flow good and services का पूरे देश के अंदर उसके बाद होगा और इसका एक और लाभ है कि जो एक बार आपने टैक्स दे दिया इनपुट के ऊपर आउटपुट के स्तर पर इसका आपको लाभ मिलने लगेगा। महंगाई के ऊपर भी लगाम लगेगी। टैक्स avoidance कठिन होगा, रेट पहले की तुलना में कम होंगे। देश की GDP को लाभ मिलेगा और जो अधिक राज्यों को और केंद्र को साधन मिलेंगे वो इस देश की गरीब की सेवा करने के लिए उनको एक अवसर उपलब्ध होगा। राज्य ने, केंद्र ने, सभी राजनीतिक दलों ने, सभी सांसदों ने सभी विधान सभाओं के सदस्यों ने, सभी राज्य सरकारों ने एकमत से इसमें कार्य किया है। मैं सबका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ■

लोकतंत्र की विरासत को हमें और सशक्त करना है: नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून को 'मन की बात' कार्यक्रम से देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि मौसम बदल रहा है। इस बार गर्मी भी बहुत रही, लेकिन अच्छा हुआ कि वर्षा ऋतु समय पर अपने नक्शे कदम पर आगे बढ़ रही है। जीवन में कितनी ही आपाधापी हो, तनाव हो, व्यक्तिगत जीवन हो, सार्वजनिक जीवन हो, बारिश का आगमन मनःस्थिति को बदल देता है।

श्री मोदी ने कहा कि आज भगवान जगन्नाथ जी की रथ-यात्रा देश के कई भागों में बहुत ही श्रद्धा और उल्लासपूर्वक देशवासी मनाते हैं। अब तो विश्व के भी कुछ भागों में भगवान जगन्नाथ जी की रथयात्रा का उत्सव सम्पन्न होता है और भगवान जगन्नाथ जी के साथ देश का ग़रीब जुड़ा हुआ है। जिन लोगों ने डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर का अध्ययन किया होगा, उन्होंने देखा होगा कि भगवान जगन्नाथ जी का मन्दिर और उसकी परंपराओं की वो बड़ी तारीफ़ करते थे, क्योंकि उसमें सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता अंतर्निहित थे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि रमजान का पवित्र महीना सब दूर इबादत में पवित्र भाव के साथ मनाया। अब ईद का त्योहार है ईद उल फित्र के अवसर पर मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं। रमजान खुशिया बांटने का महीना है। हम इन पवित्र अवसरों से खुशियां बांटते चलें।

उन्होंने कहा कि व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में कुछ भी अच्छा करना है, तो बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमारी लिखावट ख़राब है, अगर उसको ठीक करना है, तो लंबे अरसे तक बहुत जागरूक रहकर के प्रयास करना पड़ता है। तब जाकर के शरीर की, मन की आदत बदलती है। स्वच्छता का भी विषय ऐसा ही है। ऐसी बुरी आदतें हमारे स्वभाव का हिस्सा बन गई हैं। हमारी आदतों का हिस्सा बन गई हैं। इससे मुक्ति पाने के लिये अविरत रूप से हमें प्रयास करना ही पड़ेगा। हर किसी का ध्यान आकर्षित करना ही पड़ेगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अच्छी प्रेरक घटनाओं का बार-बार स्मरण भी करना पड़ेगा और मुझे खुशी है कि आज स्वच्छता ये सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा है। ये जन समाज का, जन-सामान्य का एक आन्दोलन बनता चला जा रहा है और शासन में बैठे हुए लोग भी जब जनभागीदारी से इस काम को आगे बढ़ाते हैं, तो कितनी ताक़त बढ़ जाती है।

आपातकाल की याद करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि 1975-25 जून, वो ऐसी काली रात थी, जो कोई भी लोकतंत्र प्रेमी भुला नहीं सकता है। कोई भारतवासी भुला नहीं सकता है। एक प्रकार से देश को जेलखाने में बदल दिया गया था। विरोधी स्वर को दबोच दिया गया था। जयप्रकाश नारायण सहित देश के गणमान्य नेताओं

को जेलों में बंद कर दिया था। न्याय व्यवस्था भी आपातकाल के उस भयावह रूप की छाया से बच नहीं पाई थी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अख़बारों को तो पूरी तरह बेकार कर दिया गया था। आज के पत्रकारिता जगत के विद्यार्थी, लोकतंत्र में काम करने वाले लोग, उस काले कालखंड को बार-बार स्मरण करते हुए लोकतंत्र के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे हैं और करते भी रहने चाहिए। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जेल में थे। जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया, तो अटल जी ने एक कविता लिखी थी और उन्होंने उस समय की मनःस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है।

झुलसाता जेठ मास, शरद चांदनी उदास,
झुलसाता जेठ मास, शरद चांदनी उदास।
सिसकी भरते सावन का, अंतर्घट रीत गया,
एक बरस बीत गया, एक बरस बीत गया ।।
सीखचों में सिमटा जग, किंतु विकल प्राण विहग,
सीखचों में सिमटा जग, किंतु विकल प्राण विहग।
धरती से अम्बर तक, धरती से अम्बर तक,
गूंज मुक्ति गीत गया, एक बरस बीत गया, एक बरस बीत गया ।।
पथ निहारते नयन, गिनते दिन पल-छिन,
पथ निहारते नयन, गिनते दिन पल-छिन।
लौट कभी आएगा, लौट कभी आएगा,
मन का जो मीत गया, एक बरस बीत गया ।।

श्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र के प्रेमियों ने बड़ी लड़ाई लड़ी और भारत जैसा देश, इतना बड़ा विशाल देश, जब मौका मिला तो भारत के जन-जन की रग-रग में लोकतंत्र कैसा व्याप्त है, चुनाव के माध्यम से उस ताक़त का प्रदर्शन कर दिया। जन-जन की रग-रग में फैला हुआ ये लोकतंत्र का भाव ये हमारी अमर विरासत है। इस विरासत को हमें और सशक्त करना है। ■

मनरेगा के तहत 2017-18 में 86 फीसदी मजदूरी का भुगतान समय से किया गया

मनरेगा के तहत, अप्रैल से जून 2017 में खासकर जल संरक्षण कार्यों में दिहाड़ी मजदूरों की मांग बढ़ी है। लगभग 75 करोड़ व्यक्ति के लिए पहले से ही काम उपलब्ध है और 15 जुलाई 2017 तक इसके बढ़ने की संभावना है। इसका अर्थ है कि मनरेगा के तहत देश के अलग-अलग हिस्सों में लगभग 80 लाख से 1 करोड़ लोग प्रतिदिन काम कर रहे हैं। इनमें से 86 फीसदी से ज्यादा लोगों को 15 दिन के भीतर भुगतान किया है। पिछले सालों के मुकाबले यह महत्वपूर्ण सुधार है। 99 फीसदी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (ई-एफएमएस) के जरिये किया जाता है। केन्द्र सरकार ने समय से कोष प्रदान करना सुनिश्चित किया है और राज्यों ने समय पर भुगतान करने के लिए कार्यान्वयन प्रणाली को सुदृढ़ किया।

कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर बल देने के लिए कार्यक्षेत्र पर 74 फीसदी व्यय किया जा रहा है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन ने जल संचयन और जल संरक्षण के लिए 2,264 जल ब्लॉकों पर विशेष ध्यान दिया। पूरे देश भर में वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2.62 लाख जल संरक्षण के कामों को पूरा किया गया, जिसमें 1,31,789 खेत तालाब भी शामिल है। पिछले दो वर्षों में मनरेगा ने 91 लाख हैक्टेयर से ज्यादा सिंचाई क्षमता का सृजन किया, जिसका हाल ही में आकलन आर्थिक विकास संस्थान (आईईजी), नई दिल्ली द्वारा किया गया। जिसकी रिपोर्ट 30 सितम्बर 2017 तक आने की संभावना है।

मनरेगा की 1.45 करोड़ परिसंपत्तियां भू-चिन्हित और पब्लिक डोमेन में है। आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) से पहले से ही 5.2 करोड़ कामगार जुड़े हैं और नरेगा सॉफ्ट एमआईएस में 9 करोड़ से ज्यादा कामगारों ने अपनी आधार की जानकारियों को जोड़ने पर सहमति दी। 87 फीसदी जॉब कार्डों को सत्यापित किया जा चुका है और 1.1 करोड़ जॉब कार्डों को कारणों की वजह से रद्द कर दिया गया। वंचित घरों को काम देने के लिए 89 लाख नये जॉब कार्डों के पंजीकरण को सुनिश्चित किया गया।

स्वतंत्र सामाजिक लेखा-परीक्षा इकाइयों का 24 राज्यों में गठन किया गया और राज्यों के 3100 संसाधन व्यक्तियों को सामाजिक लेखा-परीक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया गया। गांव के संसाधन व्यक्तियों के रूप में महिला स्वयं सहायता समूह को बड़े स्तर पर सामाजिक लेखा-परीक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया गया। 19 राज्यों में बेयर फूट तकनीशियनों (बीएफटी) ने कार्यक्षेत्र के स्तर पर तकनीकी सहायता का प्रशिक्षण दिया। सभी कार्यस्थलों पर सार्वजनिक सूचना और नागरिक सूचना केन्द्रों हो यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। रिकार्ड के रख-रखाव का सरलीकरण किया गया और 90 फीसदी से ज्यादा ग्राम पंचायतें सरलीकरण के लिए सात रजिस्टारों को अपना चुकी है।

मनरेगा कर्मचारियों को कौशल विकास के जरिए डीडीयूजीकेवाई के तहत दिहाड़ी मजदूरी और राज्यों में ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरईएसटीआई) बैंक श्रृंखला के जरिये स्व-रोजगार के लिए प्रभावी तरीके से काम कर रहा है। गरीबों घरों की आर्थिकी को बेहतर बनाने के लिए महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के जरिये, आजीविका की विविधता के लिए मनरेगा पर जोर दिया। ■

जल संरक्षण के लिए भारत और इजराइल के बीच एमओयू को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 जून को भारत में जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अभियान पर भारत एवं इजराइल के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी।

इससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल संरक्षित करने में देश का फायदा होगा। भारत में राष्ट्रीय जल संरक्षण अभियान को पेशेवर तरीके से डिजाइन करने, उसके कार्यान्वयन एवं निगरानी में दोनों देश राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ाने के लिए काम करेंगे। मंत्रालय निम्नलिखित उद्देश्यों को हासिल करने के लिए इस जल संरक्षण अभियान पर साथ मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए हैं:

क. भारत में जल संरक्षण को राष्ट्रीय एजेंडे में शामिल करना,
ख. हरेक नागरिक को रोजमर्रा के जीवन में पानी बचाने के लिए प्रोत्साहित करना,
ग. जल के बारे में जागरूकता पैदा करना,
घ. जल का पुनः उपयोग, पुनः संवर्द्धन एवं पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना
ड. जल संरक्षण के विषय पर वेबसाइट, मोबाइल ऐप्लिकेशन जैसे डिजिटल टूल्स विकसित करना।

हमारे सम्मानित आजीवन सदस्यगण

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत
श्री अमित शाह
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री अरुण जेटली
केंद्रीय वित्त एवं रक्षा मंत्री
श्री राधा मोहन सिंह
केंद्रीय कृषि मंत्री
श्री प्रकाश जावडेकर
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री
श्री जगत प्रकाश नड्डा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
श्रीमती मेनका संजय गांधी
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री
श्री अर्जुन राम मेघवाल
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट राज्यमंत्री
श्री विष्णुदेव साय
केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री
श्री बाबुल सुप्रियो
केंद्रीय भारी उद्योग राज्यमंत्री
श्री मनोहर पर्रिकर
मुख्यमंत्री, गोवा

श्री भूपेन्द्र यादव, सांसद
भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री
श्री अरुण सिंह
भाजपा राष्ट्रीय महासचिव
श्री शांता कुमार, सांसद
पूर्व मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश
श्री गोपाल नारायण सिंह
सांसद (राज्यसभा)
डॉ. गोकाराजू गंगा राजू
सांसद (लोकसभा)
श्री महेश पोद्दार
सांसद (राज्यसभा)
श्री अनिल शिरोले
सांसद (लोकसभा)
श्री मनोज राजोरिया
सांसद (लोकसभा)
श्री रवींद्र कुमार राय
सांसद (लोकसभा)
श्री दिलीप कुमार गांधी
सांसद (लोकसभा)
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल
राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

अमेरिका, नीदरलैंड एवं पुर्तगाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रवास की तस्वीरें

अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ

अमेरिकी उद्योगपतियों के साथ

पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के साथ

नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के साथ

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2015-17
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2015-17

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बने कमल संदेश के आजीवन सदस्य

कमल संदेश की कैशलेस सदस्यता लें!

आह्वान

आपको जानकर हर्ष होगा कि 6 दिसम्बर 2016 को पार्टी मुख्यालय में भाजपा 'कमल संदेश' का आजीवन सदस्य बनकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. **श्री अमित शाह** ने पत्रिका की सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि 'कमल संदेश' भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय पत्रिका है और यह पाक्षिक रूप में हिन्दी–अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती है।

हमारे लिए यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि मा. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं 5000/– रुपए का चैक देकर 'कमल संदेश' की आजीवन सदस्यता ली। साथ ही केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर, गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर सहित अनेक केन्द्रीय एवं प्रदेश सरकार के मंत्रियों, माननीय सांसदों, विधायकों एवं पार्टी पदाधिकारियों द्वारा आजीवन सदस्यता ग्रहण की गई है।

'कमल संदेश' हिन्दी एवं अंग्रेजी के दोनों अंकों को 5000/– (पांच हजार रुपये) की सदस्यता शुल्क देकर नियमित रूप से प्राप्त किया जा सकता है। अब 'कमल संदेश' के लिए कैशलेस भुगतान की भी सुविधा उपलब्ध है। कृपया 5000/– (पांच हजार) रुपये का योगदान कर आप भी 'कमल संदेश' (हिन्दी+अंग्रेजी) का आजीवन सदस्य बनें।

एक साल (हिन्दी/अंग्रेजी)	—	₹350/-	**तीन साल** (हिन्दी/अंग्रेजी)	—	₹1000/-
आजीवन (हिन्दी/अंग्रेजी)	—	₹3000/-	**आजीवन** (हिन्दी+अंग्रेजी)	—	₹5000/-

'कमल संदेश' के हमारे पाठकों से अनुरोध है कि इसकी सदस्यता लेकर जीवंत वैचारिक आंदोलन के भागीदार बनें।

कैशलेस बना 'कमल संदेश' सदस्य बनें और बनाएं

☞ **www.kamalsandesh.org, www.bjp.org** पर जाकर कैशलेस भुगतान क्रेडिट/डेबिट/नेटबैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं।

☞ साथ ही दिए बार कोड से मोबाइल द्वारा सीधा भुगतान भी कर सकते हैं।

chillr
ACCEPTED HERE
Scan the QR code to make a payment
Click on SCAN & PAY and enter amount
Add this contact to pay
+91 9911026172

"**कमल संदेश**" के नाम से कृपया चेक/ड्राफ्ट निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:
कमल संदेश, पीपी–66, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, सुब्रह्मण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली– 110003